भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025

सहकार से समृद्धि,
संकल्प से सिद्धि

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलें

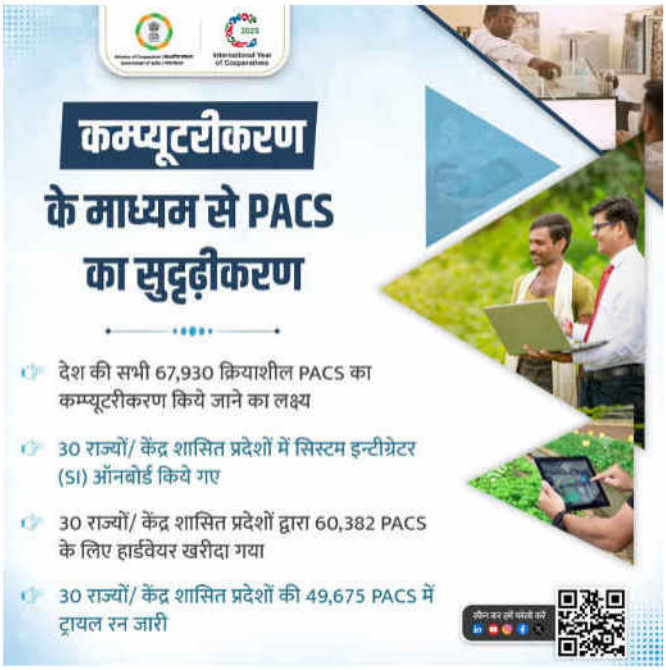

अनुक्रमणिका

अध्याय-1: भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास 1

प्राचीन काल से भारत में सहकारिता 1

स्वतंत्रता पूर्व सहकारिता का विकास 2

स्वतंत्रता के पश्चात सहकारिता का विकास 2

अध्याय 2: पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन 5

भारत में सफल सहकारी संस्थाएं 6

सहकारिता मंत्रालय की पहलें 9

अध्याय 3: विश्व में सहकारिता 13

विश्व के 10 देशों की शीर्ष सहकारी समितियां 13

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 14

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की भूमिका 14

अध्याय 4: भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 17

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम 18

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सिद्धांत 19

सहकारिता मंत्रालय की प्रस्तावित गतिविधियां 19

कुंभ में सहकारिता 23

मंत्रालयों की कार्य योजना 27

राष्ट्रीय सहकारी संघों की कार्य योजना 30

राज्यों की कार्य योजना 55

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए मीडिया प्लान 92

''एक पेड़ मां के नाम'' - वृक्षारोपण अभियान 95

वर्षांत पर कार्यवाही 96

अध्याय-1: भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास

प्राचीन काल से भारत में सहकारिता

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते।।

हजारों साल पहले लिखा गया ऋग्वेद का यह शक्तिशाली मंत्र एकता, सहयोग और साझा उद्देश्य की भावना को दर्शाता है, जो दुनिया भर में सहकारी आंदोलन को संचालित करता है। भारतीय उपनिषद, विशेष रूप से अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं और सभी लोगों के सामूहिक कल्याण के महत्व पर जोर देते हैं। संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्यांश **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** जिसका अर्थ है "विश्व एक परिवार है", भी आपसी सम्मान, साझा जिम्मेदारी और सार्वभौमिक एकजुटता के विचार को दर्शाता है।

इसी तरह **"सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु"** का अर्थ है "हम एक साथ संरक्षित हों, हम एक साथ पोषित हों" यह सहयोग और समर्थन के सिद्धांत को समाहित करता है। सामूहिक प्रयास और लाभ पर इन प्राचीन शिक्षाओं ने भारत के विकास और एकल संगठन के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।

औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने से पहले ही, भारत के कई हिस्सों में सहकारिता की अवधारणा और सहकारी गतिविधियों का प्रचलन शुरू हो गया था। ग्रामीण समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से स्थायी संपत्ति जैसे कि गांव में तालाब या गांव में जंगल बनाना, जिसे **''देवराई" या ''वनराई"** कहा जाता था, काफी आम था। इसी तरह, समूहों द्वारा संसाधनों को एकत्रित करने के उदाहरण, जैसे कि फसल के बाद खाद्यान्न को अगली फसल से पहले समूह के जरूरतमंद सदस्यों को उधार देना, या समूह के सदस्यों को उधार देने के लिए नियमित अंतराल पर नकद में छोटे-छोटे योगदान एकत्र करना, जैसे कि मद्रास प्रेसीडेंसी में चिट फंड, त्रावणकोर में **"कुरी"**, कोल्हापुर में **"भिशी"** आदि।

सन 1901 में 'अकाल आयोग' ने पारस्परिक ऋण संघों के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की, जैसा कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में लागू किया गया था। इसका विचार मजबूत संघों का निर्माण करना था, जहां लोगों के समूह मिलकर नई और मूल्यवान सुरक्षा बना सकें। ये संघ व्यक्तिगत ऋणों पर निर्भर रहने के बजाय समूह ऋण और गारंटी के लाभ प्रदान करते थे। आयोग ने कृषि बैंकों के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया।

स्वतंत्रता पूर्व सहकारिता का विकास

वर्ष 1904 में "सहकारी ऋण समिति अधिनियम" की शुरुआत के साथ भारत में सहकारी समितियां एक कानूनी इकाई बन गईं, जिसमें सहकारी समितियों के गठन, सदस्यता, पंजीकरण, सदस्यों की देनदारियों, मुनाफे के निपटान, नियम बनाने की शक्ति और विघटन के मानदंडों को रेखांकित किया गया था। हालांकि, यह प्रतिबंधात्मक था, जिसमें गैर-ऋण और अन्य समितियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था।

वर्ष 1912 के सहकारी समिति अधिनियम ने 1904 के अधिनियम की कमियों को संबोधित किया, जिसमें विपणन समितियों, हथकरघा बुनकरों और अन्य कारीगर समितियों को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार किया गया। इसके बाद 1914 में मैक्लेगन समिति ने केंद्र, प्रांत और जिला स्तरों पर तीन-स्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली का प्रस्ताव करते हुए ऋण समितियों के लिए सुधारों की सिफारिश की।

वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों को सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1925 का बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ, जो किसी प्रांतीय सरकार द्वारा पारित पहला सहकारी कानून था। वर्ष 1942 में, भारत सरकार ने कई प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम लागू किया और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की शक्ति को राज्य रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात सहकारिता का विकास

स्वतंत्रता के बाद, नई सरकारी प्रणाली का उद्देश्य आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। सहकारी समितियाँ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गईं, जिसकी शुरुआत पहली योजना से हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों के साथ उनके समन्वय पर जोर दिया गया।

वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना ग्रामीण ऋण और सहकारी विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे।

वर्ष 1984 में, भारतीय संसद ने राज्यों में सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को कारगर बनाने के लिए बहु-राज्य सहकारी संगठन अधिनियम पारित किया। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय सहकारी नीति की शुरुआत के साथ और अधिक समेकन हुआ, जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना था।

बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम एवं नियम

बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम एवं नियम, 2023 को क्रमशः 03.08.2023 और 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया था, ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, जवाबदेही बढ़ाई जा सके और चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया जा सके आदि। इसके लिए मौजूदा कानून को पूरक बनाया गया है और 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए उपरोक्त संशोधन के माध्यम से कई प्रावधान पेश किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:

1. बहु-राज्य सहकारी समितियों में चुनावों को समय पर, नियमित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारी चुनाव प्राधिकरण का प्रावधान शामिल किया गया है।
2. पारदर्शिता में सुधार के लिए, सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा सूचना अधिकारी की नियुक्ति।
3. पारदर्शिता में सुधार के लिए शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी।
4. शासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए, बहु-राज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के उन निर्णयों को शामिल किया जाएगा जो सर्वसम्मति से नहीं हैं।
5. बहु-राज्य सहकारी समितियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात को रोकने के लिए, बहु-राज्य सहकारी समिति के निदेशक उन मामलों पर चर्चा और मतदान में उपस्थित नहीं होंगे, जहां वे या उनके रिश्तेदार एक इच्छुक पक्ष हैं।
6. शासन में सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चूक या कमीशन या धोखाधड़ी के ऐसे कृत्यों को कहीं और दोहराया न जाए, निदेशकों के लिए अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं।

सहकार से समृद्धि
10,000 नवगठित
बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य
सहकारी समितियों
का
शुभारंभ
"प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति"

अध्याय 2: पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **'सहकार से समृद्धि'** की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत में पहली बार दिनांक 6 जुलाई, 2021 को एक पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। श्री अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत संरचना प्रदान करता है। सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले यह मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत था। मंत्रालय एक समावेशी, सहकार आधारित आर्थिक मॉडल की कल्पना करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत करता है।

नवगठित मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास और आर्थिक समावेशिता को बढ़ाने के लिए भारत के सहकारी क्षेत्र को ऊर्जान्वित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए डेयरी, कृषि और स्वयं सहायता समूहों जैसे किसान-केंद्रित मॉडल को बढ़ावा दे रहा है।

सहकारिता मंत्रालय ने अल्पकालिक समय में सहकारिता क्षेत्र को जीवंत एवं सशक्त बनाने हेतु कई ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें सहकारी समितियों के लिए नीतिगत सुधार और प्रौद्योगिकी उन्नयन भी शामिल है।

स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी समितियाँ ग्रामीण भारत के 98% हिस्से को कवर कर रही हैं, खाद्यान्न खरीद के मामले में 13% गेहूँ और 20% धान सहकारी समितियों से खरीदा जाता है। भारत में कुल उर्वरक उत्पादन का 25% और वितरण का 35% सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। इसी तरह, 30% चीनी उत्पादन और 20% खुदरा उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित होती हैं। 29 करोड़ के संयुक्त सदस्य आधार के साथ, जो भारत की आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है, सहकारी क्षेत्र भारत में 13% प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में योगदान देता है। भारत दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी है और कुल दूध उत्पादन का 10% से अधिक डेयरी सहकारी समितियों से आता है।

सहकारिताएँ देश के बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रमुख हैं, शहरी सहकारी बैंकों में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण सहकारी बैंकों में 6.53 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में भी सहकारी समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में, लगभग 26,000 मत्स्य सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 47 लाख है और ये मत्स्य पालकों को आजीविका प्रदान करती हैं। सहकारी समितियों की चीनी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत के कुल चीनी उत्पादन में 31% का योगदान देती है।

सहकारी विपणन समितियां और आवासन समितियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं, जबकि उपभोक्ता सहकारी समितियां, जैसे कि केंद्रीय भंडार और अपना बाज़ार, बिचौलियों को खत्म करके वस्तुओं को किफ़ायती बनाने में मदद करती हैं। हथकरघा समितियों (जैसे, एपीपीसीओ, बोयनिका) जैसी उत्पादक सहकारी समितियाँ छोटे उत्पादकों को कच्चा माल और उपकरण प्रदान करती हैं।

सहकारिता आंदोलन को मज़बूती प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 56 मुख्य पहलें की हैं जिनसे देश की सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास एवं विस्तार की नई संभावनाएँ मिल रही हैं।

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

- "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करना।
- सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों (MSCS) के विकास को सक्षम बनाना।
- देश में सहकारी आंदोलनों को सशक्त करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत संरचना प्रदान करना।
- जमीनी स्तर तक सघन करने के लिए जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को सशक्त करना।

भारत में सफल सहकारी समितियां

भारत में सहकारी संस्थाओं का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। इन संस्थाओं ने कृषि, बैंकिंग, दुग्ध उत्पादन, और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहां भारत की कुछ सफल सहकारी संस्थाओं का विवरण दिया गया है:

1. अमूल (AMUL)

स्थापना: 1946

मुख्यालय: आनंद, गुजरात

मुख्य क्षेत्र: दुग्ध और दुग्ध उत्पाद

भारत की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी सोसायटी है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में "श्वेत क्रांति" ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे अमूल ने बढ़ावा दिया और भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। डॉ. वर्गीस कुरियन को 'श्वेत क्रांति का जनक' माना जाता है उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक GCMMF के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अमूल किसानों को उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक पहुंच प्रदान करने में अग्रणी है। अमूल ब्रांड को संभालने वाली सहकारी संस्था 'गुजरात सहकारी दूध विपणन

संघ लिमिटेड (GCMMF)' है। आज अमूल का कुल कारोबार 59,545 करोड़ रुपये (7.3 बिलियन डॉलर) है और इसके पास कुल 18 जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ और 18,600 ग्राम समितियां हैं।

2. कर्नाटक मिल्क फेडरेशन

स्थापना: 1974

मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक

मुख्य क्षेत्र: दुग्ध और दुग्ध उत्पाद

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अमूल के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूध सहकारी संस्था है। यह एक दूध उत्पादकों का समूह है जो सहकारी सिद्धांतों पर काम करता है। केएमएफ की स्थापना 1974 में कर्नाटक डेयरी विकास निगम (केडीडीसी) के रूप में विश्व बैंक द्वारा संचालित डेयरी विकास परियोजना को लागू करने के लिए की गई थी। 1984 में संगठन का नाम बदलकर केएमएफ कर दिया गया। केएमएफ के कर्नाटक राज्य भर में 15 दूध संघ हैं जो प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) से दूध खरीदते हैं और 1,500 सदस्यों के साथ कर्नाटक राज्य के विभिन्न शहरी और ग्रामीण बाजारों में उपभोक्ताओं को दूध वितरित करते हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) से दूध खरीदता है और दूध को नंदिनी ट्रेडमार्क के तहत बेचा जाता है।

3. उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति

स्थापना: 1925

मुख्यालय: केरल

मुख्य क्षेत्र: श्रमिक सहकारी समिति

उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति (यूएलसीसीएस) को भारत में सबसे पुरानी श्रमिक सहकारी समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना केरल के कालीकट में वाग्भदानंद के मार्गदर्शन में की गई थी। लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ, यूएलसीसीएस ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई और पर्यटन सहित विभिन्न सरकारी विभागों के लिए निर्माण कार्य में माहिर है। यूएलसीसीएस चैरिटेबल फाउंडेशन कोझीकोड में एक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करता है जो न्यूरोडायवर्जेंट समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करता है। उरालुंगल सहकारी ने 1000 करोड़ से अधिक की राशि की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है।

4. इंडियन कॉफ़ी हाउस

स्थापना: 1936

मुख्यालय: त्रिशूर, केरल

मुख्य क्षेत्र: कॉफ़ी रेस्टोरेंट श्रृंखला

इंडियन कॉफ़ी हाउस का प्रबंधन श्रमिक सहकारी समितियों का एक समूह करता है। ये भारत में एक रेस्टोरेंट श्रृंखला है। भारत भर में इसकी मजबूत उपस्थिति है, जिसके लगभग 400 कॉफ़ी हाउस हैं। इंडिया कॉफ़ी हाउस श्रृंखला की शुरुआत 'कॉफ़ी सेस कमेटी' द्वारा सन 1936 में की गई थी, जिसका पहला आउटलेट चर्चगेट, बॉम्बे में खोला गया था और इसका संचालन 'भारतीय कॉफ़ी बोर्ड' द्वारा किया जाता था।

आज़ादी के बाद 19 अगस्त 1957 को बैंगलोर में एक सहकारी संस्था शुरू हुई। इसके बाद 27 दिसंबर 1957 को दिल्ली में भी एक संस्था स्थापित की गई। देश में कॉफ़ी हाउस चलाने के लिए 13 सहकारी समितियाँ हैं। इन समितियों का संचालन कर्मचारियों में से चुनी गई प्रबंध समितियों द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय कॉफ़ी श्रमिक सहकारी समिति संघ के तहत संबद्ध समितियाँ 17 दिसंबर 1960 को बनीं।

5. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको)

स्थापना: 1967

मुख्यालय: दिल्ली

मुख्य क्षेत्र: उर्वरक निर्माण और विपणन

भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी 'इफको' प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इफको एक बहु-राज्य सहकारी समिति है जो उर्वरक के निर्माण और विपणन में लगी हुई है। सन 1967 में 57 सदस्य सहकारी समितियों के साथ शुरू हुआ, यह आज प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2021 के अनुसार) पर कारोबार के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति है, जिसमें लगभग 35,000 सदस्य सहकारी समितियां 50 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों तक पहुँचती हैं।

यूरिया में लगभग 19% बाजार हिस्सेदारी और जटिल उर्वरकों (P2O5 शर्तों) में लगभग 31% बाजार हिस्सेदारी के साथ, इफको भारत का सबसे बड़ा उर्वरक निर्माता है। सहकारी को 2017 तक भारत के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में 66वें स्थान पर रखा गया था। वित्त वर्ष 2023 इफको का राजस्व ₹62,990 करोड़ (US$7.3 बिलियन) था, जबकि नेट इनकम ₹3,053 करोड़ (US$350 मिलियन) थी।

भारत में सहकारी आंदोलन की सफलता के मुख्य कारण

भारत में सहकारी समितियों की सफलता का श्रेय कई प्रमुख कारकों को दिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

समुदाय आधारित प्रबंधन

किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता

पारदर्शी संचालन और लोकतांत्रिक संरचना

सरकारी सहायता और नीतिगत समर्थन

सहकारी संस्थाएं न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशिता को भी सुनिश्चित करती हैं।

सहकारिता मंत्रालय की पहलें

सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचाना और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करना शामिल है। सहकारी समितियों के सशक्तिकरण, उनमें पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों की स्थापना करने, ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित के लिए विकास की पहुंच की चुनौती को पूरा करने के लिए लगातार काम करने और हर गांव को सहकारिता से जोड़ने के मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई जैसे:

प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण: (पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां, पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना, कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी), LPG डिस्ट्रीब्यूटर, पेट्रोल/डीज़ल पंप डीलर, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एवं पानी समिति के रूप में पैक्स, पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) तथा मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन, पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने

की अनुमति, बैंक मित्र सहकारी समितियों को Micro-ATMs एवं RuPay किसान क्रेडिट कार्ड, के रूप में पैक्स, पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण)

राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहु राज्यीय सहकारी समितियाँ: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) एवं सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना।

सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत: सहकारी समितियों के लिएआयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती, सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती, पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी, नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती, नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि एवं आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नगद लेनदेन में राहत।

सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण: सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023।

सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान: सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत, सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान, सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना, सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रो की स्थापना, सहकारी चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया।

सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण

सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों मे सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण

श्वेत क्रांति 2.0

आत्मनिर्भरता अभियान

सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

'सहकार से समृद्धि'
श्री अमित शाह
श्री कृष्ण पाल गुर्जर

अध्याय 3: विश्व में सहकारिता

उन्नीसवीं सदी के मध्य में यूरोप में सहकारिता के जन्म ने उद्यम के इस रूप को आंतरिक संगठन और गतिविधियों के क्षेत्रों के संदर्भ में स्थापित पूंजीवादी से अलग करके एक नया आकार दिया था। यह उन्नीसवीं सदी में सहकारिता के प्रसार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है और उन्हें मॉडल में समूहीकृत करते हुए उपभोक्ता, श्रमिक, वित्तीय और ग्रामीण सहकारी समितियां के रूप में वर्णित करता है, जो आंदोलन के मुख्य स्तंभ बने।

विश्व के 10 देशों की शीर्ष सहकारी समितियां

साल 2021 के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों और म्यूचुअल्स ने दो ट्रिलियन USD (2,409 बिलियन USD) से अधिक का कुल कारोबार किया था। ये संगठन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसमें कृषि (105 उद्यम) और बीमा (96 उद्यम) सूची में सबसे आगे हैं। थोक और खुदरा व्यापार रैंकिंग में तीसरे सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र (57 उद्यम) का प्रतिनिधित्व करते हैं। टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 300 रैंकिंग में दो वित्तीय और एक खुदरा उद्यम हैं। पहले दो स्थान फ्रेंच ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल (2021 में 117.01 बिलियन USD टर्नओवर) और जर्मन को-ऑप आरईडब्ल्यूई ग्रुप (2021 में 82.03 बिलियन USD टर्नओवर) के हैं। तीसरे स्थान पर ग्रुप बीपीसीई (2021 में 64.06 बिलियन USD टर्नओवर) है।

शीर्ष 300 उद्यमों में से अधिकांश औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका (73 उद्यम), फ्रांस (40 उद्यम), जर्मनी (31 उद्यम) और जापान (21 उद्यम) से हैं। पिछले वर्ष की तरह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कारोबार के अनुपात के आधार पर शीर्ष 300 रैंकिंग में, दो भारतीय उत्पादक सहकारी समितियां पहले और दूसरे स्थान पर पहुंची हैं: **इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरैटिव (इफको) और गुजरात कोआपरैटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरैशन लिमिटेड** पहले और दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांसीसी **ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल** है।

टर्न ओवर के आधार पर दुनिया की अग्रणी संस्थाएं निम्न हैं:

1. कृषि और खाद्य उद्योग: नॉन्गहयुप (राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ-एनएसीएफ) (कोरिया गणराज्य)

2. उद्योग और उपयोगिताएं: मोंड्रागॉन कॉर्पोरेशन (स्पेन)

3. थोक और खुदरा व्यापार: आरईडब्ल्यूई समूह (जर्मनी)

4. बीमा: टैलेंक्स समूह (जर्मनी)

5. वित्तीय सेवाएं: ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल (फ्रांस)

6. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य: सिस्टेमा यूनिमेड (ब्राजील)।

7. अन्य सेवाएं: डेटेव (जर्मनी)।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

19 जून, 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में सहकारिता वर्ष मनाने के लिए अनुशंसाएं दी गई हैं और सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित हितधारकों को इस आयोजन का उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह सदस्य देशों को IYC 2025 गतिविधियों के समन्वय और तैयारी के लिए राष्ट्रीय समितियों की स्थापना पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करता है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता में सहकारी समितियों के योगदान के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक पहल है। इसका उद्देश्य गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी मॉडल को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में महत्व देना है, साथ ही सामूहिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रेरित करना चाहता है, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य के लिए सहकारी समितियों का समर्थन और मजबूती देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनकी सेवा करता है। वर्ष 1895 में स्थापित, यह सबसे पुराने गैर-सरकारी संगठनों में से एक है और प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसके विश्व भर में 1 बिलियन सहकारी सदस्य है। यह सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष निकाय है, जिनकी संख्या विश्व भर में लगभग 3 मिलियन होने का अनुमान है, जो सहकारी समितियों के लिए और उनके बारे में ज्ञान, विशेषज्ञता और समन्वित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आवाज़ और मंच प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की भूमिका

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) अगले 12 महीनों में सहकारी समितियों की दृश्यता बढ़ाने और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाने पर ध्यान

केंद्रित करेगा। यह सहकारी समितियों के उद्यमशील परितंत्र को मजबूत करने के लिए एक सक्षम वातावरण और सहायक कानूनी और नीतिगत संरचना के निर्माण की वकालत भी करेगा। इसके अतिरिक्त, ICA का उद्देश्य क्षमता निर्माण पहल, ज्ञान साझाकरण और सहयोगी भागीदारी के माध्यम से सहकारी विकास को बढ़ावा देना है। ICA 2025 में सहकारी आंदोलन में युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें शामिल करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना भी बना रहा है।

SHRI NARENDRA MODI
HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA
25th November, 2024 | Bharat Mandapam, New Delhi
ICA
IFFCO

INAUGURATION
OF THE ICA GLOBAL COOPERATIVE CONFERENCE 2024
&
THE LAUNCH OF
International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World
BY
SHRI NARENDRA MODI
HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA
25th November, 2024 | Bharat Mandapam, New Delhi
SHRI AMIT SHAH
Government of India
H.E. DASHO TSHI
IFFCO
ICA

अध्याय 4: भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के **''अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025"** का भी शुभारंभ किया और अन्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो व एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में 100 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकारिता के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इसके अलावा भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, 8 लाख सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं का आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ***''यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो भारत के सहकारी आंदोलन के विस्तार के साथ मेल खाता है। उन्होंने भारत में सहकारी समितियों के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि सहकारी समितियां दुनिया के लिए एक आदर्श हैं और भारतीय संस्कृति व जीवन शैली की नींव हैं"।***

प्रधानमंत्री ने कहा कि, कैसे सहकारी समितियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण दिया। उन्होंने सरदार पटेल जैसे नेताओं की विरासत की प्रशंसा की, जिन्होंने दुग्ध सहकारी समितियों अमूल जैसी संस्थाओं की नींव रखी, जो अब एक वैश्विक ब्रांड है। भारत की सहकारी समितियां एक विचार से एक आंदोलन, एक आंदोलन से क्रांति और अंत में सशक्तीकरण तक विकसित हुई हैं।

श्री मोदी जी ने भारत की सहकारी उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि ***''देश में 8 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जो ग्रामीण भारत के 98% हिस्से को कवर करती हैं और 30 करोड़ लोगों को शामिल करती हैं। उन्होंने चीनी, उर्वरक, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की भूमिका की प्रशंसा की, जहां 2 लाख से अधिक आवास सहकारी समितियाँ संचालित होती हैं। ''***

प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने के लिए किए गए प्रमुख सुधारों पर भी प्रकाश डाला जैसे कि इन बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में लाना और जमा बीमा को बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये करना। उन्होंने इस क्षेत्र की वृद्धि का उल्लेख किया, जहां अब सहकारी बैंकों में 12 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जो जनता के विश्वास को दर्शाता है।

श्री मोदी ने सहकारी समितियों को बदलने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसमें एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, नए मॉडल उपविधियों, आईटी एकीकरण और 2 लाख गांवों में बहुउद्देशीय समितियां शामिल हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसी पहलों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना है। ONDC और GeM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी समितियों को अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने में सक्षम बना रहे हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों में महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें 60% से अधिक भागीदारी महिलाओं की रही।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि ***''संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय समयानुकूल कदम है और यह दुनिया भर के लाखों गरीबों और किसानों के लिए वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का उद्घाटन और भारत में आईसीए के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन की मेजबानी एक स्वागत योग्य कदम है''।***

भूटान के प्रधानमंत्री श्री दाशो शेरिंग तोबगे ने कहा, ***"हम देश के दक्षिण में एक ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं जो विचारशीलता और नवीन सोच पर आधारित हो-यह मानव-केंद्रित सहकारी मूल्यों के अनुरूप है।"***

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसकी थीम है **''सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है"** जो हर जगह सहकारिता के स्थायी वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। यह थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सहकारी मॉडल कई वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक आवश्यक समाधान है और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को लागू करने के प्रयासों को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 सहकारी समितियों के मूल्यों और सिद्धांतों का जश्न मनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए वैश्विक रूप से एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। IYC 2025 के लिए नियोजित कार्यक्रमों और पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रमुख संगठनात्मक सिद्धांतों के साथ संरेखित हों। ये सिद्धांत पूरे वर्ष कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों के संगठन और क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सहकारी मूल्यों के वास्तविक सार को दर्शाते हैं। **अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है-**

जागरुकता बढ़ाना: सतत विकास में सहकारी समितियों के योगदान पर प्रकाश डालना।

विकास को बढ़ावा देना: सहकारी समितियों के लिए उद्यमशीलता पारितंत्र को मजबूत करना।

सहायक अवसंरचना की वकालत करना: सहकारी समितियों के लिए सक्षम कानूनी और नीतिगत वातावरण बनाना।

नेतृत्व को प्रेरित करना: उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देना और सहकारी आंदोलन में युवाओं को शामिल करना।

क्षमता निर्माण का समर्थन करना: सहकारी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना और साझेदारी बनाना।

सहभागी निर्णय लेना: सदस्यों को सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देना।

समुदाय के प्रति सरोकार: सहकारी समितियों के भीतर समुदाय के सरोकार को बढ़ावा देना।

समानता: सहकारी समितियों के भीतर समानता सुनिश्चित करना।

एकजुटता: सहकारी समितियों के भीतर एकजुटता को बढ़ावा देना।

सहयोग: सहकारी समितियों के भीतर सहयोग को प्रोत्साहित करना।

सहकारिता मंत्रालय की प्रस्तावित गतिविधियां

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान मोदी सरकार एक नई सहकारिता नीति लाकर भारत के 'सहकारिता आंदोलन' को एक नया आयाम प्रदान करेगी । प्रधानमंत्री मोदी के **"सहकार से समृद्धि"** की परिकल्पना के तहत लाखों ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों

की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियां किसानों को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगी। इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने और तकनीकी रूप से कुशल बनाने के लिए जल्द ही एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय ने अगले 3 सालों में भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी निकाय बनाने का लक्ष्य भी रखा है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में, भारत एक आधुनिक सहकारी संरचना की ओर बढ़ रहा है जो दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग कर रहा है। यह दृष्टिकोण डिजिटल अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप है, जो सुनिश्चित करता है कि सहकारी समितियां बदलते समय में अनुकूलनीय और प्रभावी बनी रहें।

भारत में सहकारिता वर्ष के दौरान सभी गतिविधियां निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप आयोजित की जाएंगी-

1. पारदर्शिता
2. जवाबदेही
3. परिचालन दक्षता
4. नीतिगत सुधर
5. सहयोग तंत्र को बढ़ावा
6. सहकारी संस्थाओं के इतिहास और पारंपरिक शक्ति का प्रदर्शन
7. बहु-उद्देशीय PACS के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण
8. सहकारी क्षेत्र युवाओं और महिलाओं की भागीदारी
9. सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण को पुनर्परिभाषित कर उत्कृष्ठत संस्थानों का विकास

सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2025 में सहकारिता के वैश्विक लाभों पर प्रकाश डालेगा, अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय/राज्य सहकारी संघों, बहुराज्यीय सहकारी समितियों एवं अन्य सभी हितधारकों के सहकार से राज्य, जिला, और स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना है.

ग्रामीण स्तर पर:

- PACS/ प्राथमिक सहकारी समितियों में बोर्ड बैठकें, लेखांकन, लेखा प्रशिक्षण, सदस्यता अभियान, बिजनेस में लाना एवं मॉडल सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।

- नए बहुउद्देशीय PACS बनाए जाएंगे।
- कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रशिक्षण एवं सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।
- कृषि क्षेत्र में नई ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा।
- बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा FPO प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा एफपीओ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों में युवाओं/महिलाओं/विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- मंत्रालय के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सहकारिता गीत, सहकारिता में सफलता की कहानियां, युवा सहकारिता तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य और जिला स्तर पर:

- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक: बोर्ड बैठकें, लेखांकन, लेखा प्रशिक्षण, सदस्यता अभियान, बिजनेस में लाना, माइक्रो-एटीएम वितरित किए जाएंगे।
- सहकारिता से संबंधित स्थानीय प्राथमिकता मुद्दों पर बैठकें/सम्मेलन/विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सभी दुग्ध संघों द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, व्यापार विस्तार पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
- सभी राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के मुख्य कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन एवं निगरानी की जाएगी।
- राज्य/जिला स्तर पर सहकारी धरोहर की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।
- मंत्रालय के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- सभी राज्यों के राजभवनों में सहकारिता महोत्सव मनाया जाएगा।
- कार्यक्रमों में अधिक से अधिक युवाओं/महिलाओं/विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- सहकारिता गीत, सहकारिता में सफलता की कहानियां, युवा सहकारिता तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय/राज्यों के सहकारी संघ एवं बहु-राज्यीय सहकारी समितियां:

- सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों में भागीदारी की जाएगी।
- बेस-लाइन बनाकर एक वर्ष में प्रस्तावित प्रगति/उपलब्धियों का प्रतिवेदन बनाकर कार्यान्वित किया जाएगा।

- गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।
- सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत और कानूनी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे।
- देश और विदेश की सहकारी समितियों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यों को साझा किया जाएगा।
- मंत्रालय के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- राज्य/जिला स्तर पर सहकारी धरोहर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा:

- विभिन्न कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन (ग्रामीण, जिला/राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर) किया जाएगा।
- बहुउद्देशीय PACS हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सहकारिता वर्ष के दौरान, नवगठित 10,000 बहुउद्देशीय पैक्स डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की हैंड होल्डिंग एवं उनके व्यवसाय में विविधीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- प्रशिक्षण केंद्रों का विकास किया जाएगा।
- कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- विशेषज्ञों द्वारा संपादकीय लेख प्रकाशित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर:

- 9 सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण शहरों में सम्मेलन/राष्ट्रीय सेमिनार (फरवरी-नवंबर तक प्रति माह 2 सम्मेलन) आयोजित किए जाएंगे।
- मंत्रालय के स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सहकारिता के माध्यम से अभिसरण पर केंद्रित कम से कम दो अंतर-मंत्रालयी अथवा अंतर-विभागीय सम्मेलन (NABARD, NDDB, NFDB, Meity, DAFW, DFPD) आयोजित किए जाएंगे।
- दिसंबर महीने में पुरस्कार एवं समापन समारोह आयोजित किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का जश्न मनाने के लिए मंत्रालयों और राज्यों के अलावा राष्ट्रीय सहकारी संघों द्वारा भी पूरे सालभर की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

कुंभ में सहकारिता

भारत सरकार द्वारा 'महाकुंभ 2025' के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। महाकुंभ में अमूल, नेफेड, एनसीएल, बीबीएसएसएल ने भी अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए हैं। इनके जरिए भारत ब्रांड के तहत ऑर्गेनिक उत्पादों, बीजों, आदि की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है।

महाकुंभ में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे कुछ प्रयास:

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSL) के साथ संयुक्त रूप से स्थापित 'सहकारिता मंडप' का उद्देश्य सामुदायिक विकास और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में सहकारी पहलों के महत्व को प्रदर्शित करना है। यह मंडप हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा समर्थित "सहकारिता के बीच सहयोग" के लोकाचार का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सहकारिता नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम NCOL की आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कार्य योजना का हिस्सा है।
- महाकुंभ 2025 में नेफेड द्वारा 'मोबाइल वैन' के माध्यम से 'भारत ब्रांड' के तहत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री प्रारंभ की जा रही है। यह सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि उन्हें शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आसानी से मिल सकें।
- महाकुंभ में, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) अपने 50 अमूल पार्लरों के माध्यम से आईवाईसी को बढ़ावा देगा, जो 45 दिनों में 45 करोड़ उपस्थित लोगों को दृश्यता प्रदान करेगा।
- NCEL, BBSSL और NCOL के साथ मिलकर स्टॉल लगाए हैं। इनके जरिए भारत ब्रांड के तहत ऑर्गेनिक उत्पादों, बीजों, आदि की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है।

NAFED WELCOMES
YOU TO KUMBH
RELIEF TO CONSUMERS
RELIEF TO CONSUMERS

nafed

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
NATIONAL COOPERATIVE ORGANICS LIMITED
BHARAT के किसान से, BHARAT के दाम में
ATTA | JAGGERY | SPICES | PULSES

सहकार से समृद्धि
सहकारिता का संगम
संकल्प से सिद्धि

मंत्रालयों की कार्य योजना

राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति (एनईसी) का गठन

सहकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) 2025 के लिए गतिविधियों की योजना, समन्वय और निष्पादन की देखरेख के लिए सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में आईवाईसी-राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति (एनईसी) की स्थापना की है। प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और हितधारक संगठनों के प्रमुखों वाली यह समिति रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर आईवाईसी गतिविधियों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

समिति आईवाईसी-2025 के उत्सव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी गतिविधियों की समग्र योजना, समन्वय और कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। समिति आईवाईसी-2025 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों, सीखों और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना की सिफारिशों का सारांश देते हुए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी।

एनईसी समिति के सदस्य

1. सचिव सहकारिता - अध्यक्ष
2. सचिव उर्वरक- सदस्य
3. सचिव कृषि एवं किसान कल्याण- सदस्य
4. सचिव ग्रामीण विकास- सदस्य
5. सचिव वित्त- सदस्य
6. सचिव आर्थिक संबंध- सदस्य
7. सचिव विदेश- सदस्य
8. सचिव वाणिज्य- सदस्य
9. सचिव मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी- सदस्य
10. सचिव उपभोक्ता मामलें - सदस्य
11. सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण- सदस्य
12. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य
13. सचिव सूचना एवं प्रसारण- सदस्य
14. सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस- सदस्य

15. सचिव खाद्य प्रसंस्करण- सदस्य

16. सचिव जल शक्ति- सदस्य

17. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड- सदस्य

18. महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)- सदस्य

19. अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)- सदस्य

20. सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ- सदस्य

21. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)- सदस्य

22. मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) – सदस्य

23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) – सदस्य

24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) – सदस्य

25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) – सदस्य

26. संयुक्त सचिव (सीटीपी), सहकारिता मंत्रालय – संयोजक

27. किसी भी अन्य सदस्य को, जिसे उचित समझा जाए, समिति में आमंत्रित किया जा सकता है।

समिति की प्रमुख जिम्मेदारियों में कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका समन्वय करना, उद्घाटन और समापन समारोह आयोजित करना, तथा वैश्विक समारोहों को सहकारी सिद्धांतों के साथ जोड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल है। सूचना के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न चैनलों के माध्यम से IYC पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मीडिया योजना विकसित की गई है। सहकारी क्षेत्र के भीतर जवाबदेही और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने के लिए, NEC सहकारी प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रैंकिंग ढांचा स्थापित करेगा और सहकारी समितियों और व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार शुरू करेगा। चुनौतियों का समाधान करने और IYC लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रगति समीक्षा की जाएगी और मासिक रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालयों और संगठनों को कई तरह की पहलें करने का अनुरोध किया गया है:

- AS/JS या समकक्ष के पद पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, ताकि विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
- सहकारी उत्पादों की पैकेजिंग, आधिकारिक लेटरहेड, पत्राचार, ईमेल और वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया हैंडल पर IYC लोगो का उपयोग।
- प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर IYC लोगो और प्रचार सामग्री प्रदर्शित किए जाने की योजना, और सभी मंत्रालयों के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने संचार में लोगो को शामिल करना चाहिए।
- CSC केंद्र IYC लोगो और नियमित पोस्ट के लिए अपने आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करेंगे।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक व्यापक मीडिया योजना विकसित करने के लिए PIB टीम के साथ काम करेगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय FPO और अन्य ग्राम-स्तरीय संगठनों में कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- पशुपालन और डेयरी मंत्रालय डेयरी सहकारी समितियों को शामिल करेगा, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को विभिन्न आयोजनों में एफपीओ और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- विदेश मंत्रालय IYM की तर्ज पर विदेश स्थित मिशन को भी कवर करेगा
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चीनी मिलों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में कार्यक्रमों का आयोजन
- एनडीडीबी द्वारा हीरक जयंती और अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों का आयोजन
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने नियमित कार्यक्रमों में सम्मलेन को शामिल करेगा, और लाइव कार्यक्रमों और सफलता की कहानियों के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- जिसमें डीडी न्यूज़ और यूट्यूब जैसे अन्य इन-हाउस प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट शामिल है। इसके अलावा, प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियों को सोशल मीडिया के साथ-साथ डीडी किसान और आकाशवाणी पर प्रसारित करेंगे, ताकि दृश्यता और सहभागिता बढ़ाई जा सके।

सभी मंत्रालय और विभाग इन गतिविधियों के निष्पादन में संरेखण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय सहकारी संघों की कार्य योजना

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने एवं गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए देश के राष्ट्रीय सहकारी संघों द्वारा उनकी कार्ययोजना मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं । सभी संस्थाएं सालभर बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नई नई योजनाओं का विस्तार करेंगी । अन्य संघों द्वारा भी उनकी कार्य योजना भी भेजी जा रही हैं।

1. NAFCARD

नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड (NAFCARD) की स्थापना 1988 में हुई थी। यह अखिल भारतीय सहकारी केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों से विकसित हुआ, जिन्होंने 1959 में भारत में भूमि बंधक बैंकों के संचालन का समन्वय करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1960 में अखिल भारतीय केंद्रीय भूमि बंधक बैंक सहकारी संघ की स्थापना हुई, जिसने दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (LTCCS) को बढ़ावा दिया।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

राष्ट्रीय स्तर पर:

- **अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौरा**: ICA-AP क्रेडिट और बैंकिंग कमेटी के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में 20 प्रतिभागियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभागी स्ववित्त पोषण के आधार पर भाग लेंगे, और फेडरेशन स्थानीय आतिथ्य की व्यवस्था करेगा।
- **वेबिनार**: 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय (MOC) के स्थापना दिवस और अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे। थीम होगी: **"सहकार से समृद्धि: MOC द्वारा लिए गए पहल"।**
- **IYC 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन**: नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें उत्कृष्ट SCARDBs और PCARDBs को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 800-900 प्रतिभागी भाग लेंगे।

***स्रोत**: NAFCARD द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

2. NAFSCOB

नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (NAFSCOB) की स्थापना 19 मई 1964 को राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों का समर्थन करने और भारत में लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना (STCCS) के विकास के लिए की गई थी। यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है और पिछले 60 वर्षों से ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली की सेवा कर रहा है।

मार्च 2023 तक, NAFSCOB में 33 राज्य सहकारी बैंक (SCBs), 351 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCBs), और 1,06,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) शामिल हैं, जिनकी कुल कार्यशील पूंजी ₹14,73,428.96 करोड़ है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- ग्रामीण सहकारी बैंकों के हितधारकों को नई दिल्ली एक्शन एजेंडा और IYC स्टाम्प उपयोग के बारे में सूचित करना, साथ ही अमृत काल (2022-2047) के दौरान STCCS व्यापार योजनाओं के विस्तार पर अध्ययन के लिए MOC की स्वीकृति प्राप्त करना। यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित होगा (संभावित) और 800 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- फरवरी में सदस्यता अभियान और IYC 2025 कार्यान्वयन पर चर्चा ICA ग्लोबल ऑफिस के साथ की जाएगी। NAFSCOB और ICBA के सहयोग से नेतृत्व और सहकारी पहचान को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यक्रम मुंबई और ब्रसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित होगा, जिसमें 800 प्रतिभागी होंगे।
- ICA 2026-2030 रणनीति कार्यशाला और पहला IYC 2025 कार्यक्रम NEDAC, APRACA और ICBA के साथ मुंबई और ब्रसेल्स में आयोजित होगा, जिसमें NAFSCOB का IYC 2025 एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा (100 प्रतिभागी)।
- दूसरा IYC 2025 कार्यक्रम, MOC के साथ एक्शन प्लान समीक्षा, और सेविले (स्पेन) में ICBA के विकास के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम में भागीदारी। इसमें मुंबई और सेविले में 250 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- SDGs, डिजिटलीकरण, और वित्तीय समावेशन की समीक्षा, साथ ही ICA GA बैठक मैनचेस्टर (यूके) में, जिसमें मुंबई और मैनचेस्टर के 150 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- PACS के लिए मॉडल HR नीति पर विचार-विमर्श और STCCS को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
- चौथा IYC 2025 कार्यक्रम और बोर्ड की बैठक श्रीलंका में आयोजित होगी, जिसमें मुंबई (संभावित) और श्रीलंका में 100 प्रतिभागी शामिल होंगे।

- IYC का समापन समारोह MOC, STCCS, और राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ समन्वय में आयोजित किया जाएगा।

स्रोत: *NAFSCOB द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

3. NCDFI

नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCDFI) की स्थापना 7 दिसंबर 1970 को हुई थी। यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। यह भारत में डेयरी सहकारी समितियों का शीर्ष संगठन है, जिसमें 28 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, 240 जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, 2.30 लाख ग्राम स्तरीय दूध उत्पादक सहकारी समितियां, और 180 लाख डेयरी किसान सदस्य शामिल हैं।

NCDFI का मुख्य उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों के संचालन को समन्वय, नेटवर्किंग और वकालत के माध्यम से सुविधाजनक बनाना है। यह रक्षा मंत्रालय और IRCTC जैसे संगठनों को दूध और डेयरी उत्पादों की संस्थागत बिक्री का समन्वय करता है। इसके अलावा, NCDFI श्रेष्ठ पशु आनुवंशिकी (SAG) सीमेन डोज़ के माध्यम से आनुवंशिक सुधार में सहायता करता है, सहकारी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- डेयरी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना: 2025 एजेंडा का मुख्य उद्देश्य होगा।
- 51वें डेयरी उद्योग सम्मेलन (DIC): यह पटना, बिहार में आयोजित होगा, जिसमें 20,000 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना है। इसमें डेयरी सहकारी समितियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय डेयरी सहकारी बैठक या डेयरी लीडर्स डायलॉग: यह आनंद, गुजरात में NCDFI कार्यालय परिसर के उद्घाटन और NCDFI पुरस्कार प्रस्तुति के साथ आयोजित होगी। कार्यक्रम का विषय होगा: "डेयरी सहकारी समितियां बेहतर आजीविका और पोषण का निर्माण करती हैं"।

- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति: संस्थानों जैसे रक्षा बलों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम: वर्षभर जागरूकता कार्यक्रम और संवाद आयोजित होंगे। NCDFI संचार में IYC लोगो प्रदर्शित किया जाएगा, और सदस्य सहकारी समितियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- युवाओं की भागीदारी: छात्रों के लिए NAARM और VAMNICOM जैसे संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारी विकास पर केंद्रित MBA छात्रों के लिए इंटर्नशिप और डेयरी सहकारी समितियों के अध्ययन दौरे आयोजित किए जाएंगे।

स्रोत: *NCDFI द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

4. NCEL

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना 25 जनवरी, 2023 को भारत सरकार के सहयोग से की गई थी। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा परिकल्पित, एनसीईएल पूरे भारत में सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है।

जीसीएमएमएफ (अमूल), इफको, कृभको, नेफेड और एनसीडीसी जैसी अग्रणी सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित एनसीईएल खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, प्रमाणन और व्यापार के माध्यम से भारत की सहकारी निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संगठन सहकारी संस्थाओं को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से निर्यात-संबंधी लाभों तक पहुँचने में मदद करता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और सदस्यों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- ग्रामीण वॉयस पत्रिका (हिंदी और अंग्रेजी) का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में एक स्टॉल स्थापित किया जाएगा, जिसमें 50-80 लाख प्रतिभागियों के आने की संभावना है।

- BPO आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से 67,000 सहकारी समितियों को जोड़ा जाएगा।
- महाराष्ट्र में NCEL मास्कॉट का शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, महाराष्ट्र नोडल एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर और बांस के पौधों के रोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2,000-5,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज़लेटर भी प्रकाशित किया जाएगा।
- नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस (5 जुलाई) और सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस (6 जुलाई) के अवसर पर एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें NCEL के AI एडवाइजर/इन्फ्लुएंसर और सहकारी मार्क/प्रमाणन का शुभारंभ होगा।
- युवा आउटरीच कार्यक्रम: भारतीय सहकारी आंदोलन पर आधारित एक वर्चुअल म्यूजियम और डाउनलोड करने योग्य रंगीन किताब लॉन्च की जाएगी, जिसमें 200-500 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में ODOP मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1,000-2,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान निर्यात एंबेसडर कार्यक्रम और IYC गतिविधियों की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाएगा।

स्रोत: *NCEL द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

5. NFCSF

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF) की स्थापना 1960 में हुई थी, और यह भारत भर में सहकारी शुगर मिलों और राज्य फेडरेशनों के संचालन का समन्वय और समर्थन करता है। यह 269 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 260 सहकारी शुगर मिलें और 9 राज्य फेडरेशन शामिल हैं, जो मिलकर 52 लाख से अधिक गन्ना उगाने वाले किसानों की सेवा करते हैं। NFCSF भारत की कुल चीनी उत्पादन में लगभग 31% का योगदान करता है।

NFCSF का मुख्य उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देना है, साथ ही संचालन की दक्षता में सुधार और नए सहकारी शुगर मिलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी समर्थन और शोध प्रदान करना है। यह सदस्य मिलों द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियों के समाधान के लिए शोध, सम्मेलन और सेमिनारों का आयोजन भी करता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF) ने IYC 2025 के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसमें वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और आउटरीच गतिविधियों का समावेश है।
- राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मुख्य अतिथि होंगे और 1,200 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।
- पंजाब में कार्यशालाएँ और गुजरात में मॉडल बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी, और इसका बजट ₹20 लाख होगा।
- महाराष्ट्र में शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिभागी शामिल होंगे, साथ ही महाराष्ट्र में मॉडल एजीएम आयोजित होगी, जिसमें 3,000 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- पूरे वर्षभर, NFCSF एक वृक्षारोपण अभियान चलाएगा, सहकारी ध्वज को फहराएगा, और एक मीडिया योजना लागू करेगा, जिसमें पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, और डिजिटल मीडिया शामिल हैं।
- अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना, शाहूनगर शेंद्रे सातारा में वर्ष भर रक्तदान, साइकिल रैली, किसान सभा, स्लोगन, निबंध, चित्र कला प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपने विभिन्न पत्र व्यवहारों में IYC लोगो (Logo) का प्रचार-प्रसार।

स्रोत: *NFCSF द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

6. NLCF

नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NLCF) की स्थापना 1981 में हुई थी, और यह भारत में श्रमिक सहकारी आंदोलन का शीर्ष निकाय है, जो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) एक्ट के तहत पंजीकृत है। NLCF का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से एससी/एसटी, ओबीसी और आदिवासी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 45,232 श्रमिक ठेका/निर्माण सहकारी समितियों और 2,084 वन श्रमिक सहकारी समितियों का

पर्यवेक्षण करता है, जिसमें 216 जिलों और 19 राज्य फेडरेशनों में 28 लाख श्रमिक सदस्य हैं। इसमें कुल 700 प्रतिभागी भाग लेंगे।

NLCF की गतिविधियों में सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता, प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, मॉडल बाय-लॉ प्रदान करना और सरकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है और सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- मार्च 2025 में दिल्ली में एक ऑल-इंडिया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 150 प्रतिभागियों की भागीदारी होगी।
- पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के श्रमिक सहकारी समितियों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला ACSTI, शिमला में आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 100 प्रतिभागियों के लिए एक सदस्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ICM, देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
- सितंबर 2025 में दिल्ली में एक और ऑल-इंडिया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 150 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- इसके बाद, महाराष्ट्र (नवंबर) और केरल (दिसंबर) में 100-100 प्रतिभागियों के लिए इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्रोत: *NLCF द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

7. NAFED

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। कृषि किसान नेफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नेफेड के कामकाज में आम सभा के सदस्यों के रूप में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें कुल 1800 प्रतिभागी भाग लेंगे।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- IYC लोगो को आधिकारिक संवाद और सोशल मीडिया में एकीकृत करना, सहकारिता मंत्रालय और फेडरेशनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी करना।
- NAFED गुजरात और महाराष्ट्र में 50 NAFED बाजार फ्रेंचाइजी के साथ सहकारी सदस्य समितियों को समर्थन प्रदान करेगा, साथ ही राज्य स्तर पर क्विज, बहस और खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। विभिन्न राज्यों में नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया प्रमोशन भी किए जाएंगे।
- NAFED प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सहकारी लेखों को बढ़ावा देगा, त्रैमासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करेगा, और कई राज्यों में स्थानीय खेल आयोजनों का आयोजन करेगा।
- कृषि के सर्वोत्तम अभ्यास और क्षमता निर्माण पहलों पर वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जो भारत भर के प्रतिभागियों को जोड़ेंगे।
- राष्ट्रीय बहस प्रतियोगिता, इसके बाद 100 NAFED बाजार फ्रेंचाइजी सहकारी सदस्य समितियों के लिए, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- NAFED मुख्य कार्यालय में क्विज प्रतियोगिताएँ और एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
- अगस्त में, NAFED 500 नई बाजार फ्रेंचाइजी लॉन्च करेगा, साथ ही वृक्षारोपण पहलों और वेबिनार का आयोजन करेगा। उत्तर-पूर्व में Fish FPOs द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाएगा।
- सहकारी उत्पादों के हैम्पर का वितरण, इसके बाद सोशल मीडिया प्रमोशन और सहकारी आंदोलन पर लेख प्रकाशित किया जाएगा।
- सहकारी सदस्य समितियों और FPOs का समर्थन साथ ही मीडिया आउटरीच और सोशल मीडिया प्रमोशन जारी रहेगा।

स्रोत: *NAFED द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

8. IFFCO

3 नवंबर, 1967 को स्थापित भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जिसका पूर्ण स्वामित्व कृषि सहकारी समितियों के पास है। शुरुआत में इसमें 57 सदस्य समितियां शामिल थीं, लेकिन अब यह 35,667 सदस्य समितियों को सेवाएं प्रदान करती है, तथा लगभग 5 करोड़ किसानों तक पहुंचती है।

इफको ने पिछले 23 वर्षों से लगातार अपने सदस्यों को 20% लाभांश का भुगतान किया है और टर्नओवर-टू-जीडीपी अनुपात के आधार पर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा इसे दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है।

इफको की सदस्यता में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की कृषि सहकारी समितियाँ शामिल हैं, जिनमें से 80% प्राथमिक स्तर पर हैं। इसका मुख्य व्यवसाय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक वितरित करना है। सहकारी समिति भारत भर में पाँच अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र संचालित करती है और ओमान, जॉर्डन, सेनेगल और दुबई में इसकी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है।

इफको ने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बीमा, कृषि रसायन, ग्रामीण वित्त और विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में विविधता लाई है। इसने हाल ही में इफको नैनो यूरिया प्लस और इफको नैनो डीएपी जैसे अभिनव उत्पाद पेश किए हैं, जो पारंपरिक उर्वरकों के लिए जैव-सुरक्षित विकल्प हैं।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

2025 में सहकारिता की वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और नवाचार के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करते हुए एक श्रृंखला प्रभावशाली राष्ट्रीय-स्तरीय घटनाएँ और पहल योजनाबद्ध की गई हैं। इनमें शामिल हैं:

- IFFCO के 50 वर्षों का उत्सव – IFFCO अपनी कलोल प्लांट पर पांच दशकों की सफलता का जश्न मनाएगा, जिसमें 3,000 प्रतिभागी होंगे, और इस प्लांट को किसानों और सहकारी समितियों के नाम समर्पित किया जाएगा।
- कार्बन-न्यूट्रल पहलों और नीम किस्मों में सुधार के तहत पश्चिम बंगाल या असम में 5,000 प्रतिभागियों के साथ एक 10 लाख वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी।
- लखनऊ में एक भव्य सहकारी सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें उत्तरी और हिंदी भाषी राज्यों से 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विषयों पर मासिक वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जिनका कुल दर्शक संख्या 5,000 होगी, ताकि ज्ञान-साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
- सहकारी समितियों में सदस्यता को 35,600 से बढ़ाकर 40,000 करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 55,000 करने का लक्ष्य है।

- वृक्षारोपण पहल को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख पेड़ किया जाएगा, जो पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा।

स्रोत: *IFFCO द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

9. BBSSL

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), जो 25 जनवरी, 2023 को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हुई, का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। यह बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, जिससे खेती में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

इफको, कृभको, नैफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बीबीएसएसएल सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से बीज उत्पादन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। इसके उद्देश्यों में बेहतर बीज उपलब्धता सुनिश्चित करना, छोटे किसानों को सहायता प्रदान करना और पारंपरिक और उन्नत दोनों प्रकार के बीजों को बढ़ावा देना शामिल है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

आईवाईसी-2025 के लिए नियोजित गतिविधियों में सहकारी विकास, पर्यावरण संरक्षण और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

- BBSSL के लिए सदस्यता अभियान 10 शहरों में 12 क्लस्टरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य वर्ष के अंत तक सदस्यता को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करना है।
- पंतनगर/देहरादून में पारंपरिक बीज सेमिनार (राष्ट्रीय स्तर) आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 वक्ता और 1,000 प्रतिभागी शामिल होंगे, जबकि महाकुंभ में प्रयागराज में सब्जी बीजों की बिक्री के तहत 3,000 बीज पैकेट वितरित किए जाएंगे।
- 20 वृक्षारोपण ड्राइव आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक कार्यक्रम में 200 पेड़ लगाए जाएंगे, और कुल अनुमानित सहभागिता 15,000 से अधिक व्यक्तियों की होगी, जो स्थिरता, सहकारी विकास और कृषि उन्नति के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्रोत: *BBSSL द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

10. KRIBHCO

कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO), जिसे 1980 में स्थापित किया गया था, एक प्रमुख उर्वरक उत्पादक है, जिसमें मार्च 2024 तक 9,650 सदस्य सहकारी समितियां और 390.78 करोड़ रुपये का भुगतान पूंजी है। इसकी शुद्ध संपत्ति 2023 में 5,128.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 5,311.01 करोड़ रुपये हो गई। KRIBHCO गुजरात के हजीरा में एक यूरिया संयंत्र संचालित करता है, जिसका अमोनिया के लिए क्षमता उपयोग 111.32% और यूरिया उत्पादन के लिए 106.4% है। यूरिया के अलावा, यह तरल जैव उर्वरक और प्रमाणित बीज भी उत्पादित करता है, जिन्हें विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों और खुदरा आउटलेट्स के माध्यम से विपणन किया जाता है। कंपनी निंबू कोटेड यूरिया, जैव उर्वरक, हाइब्रिड बीजों का निर्माण करती है और KRIBHCO एग्री बिजनेस लिमिटेड और KRIBHCO ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियों में विविधीकरण किया है। KRIBHCO कृषि निर्यात को भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से बढ़ावा भी देता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- राष्ट्रीय स्तर पर, प्रयागराज कुम्भ मेला में KRIBHCO उत्पादों की प्रचार-प्रसार, जिसमें 5 करोड़ पर्यटकों का आगमन होगा।
- सूरत में 10,000 प्रतिभागियों के लिए एक मेगा सहकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और राज्य स्तर पर सहकारी समाज/कृषि यात्रा आयोजित की जाएगी जिसमें 50 प्रतिभागी होंगे, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर में सहकारी प्रदर्शनी और नेता समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें 5,000 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- साल भर की गतिविधियों में वृक्षारोपण अभियान, सहकारी शिक्षा सम्मेलन, समिति गोद लेने के कार्यक्रम और ग्रामीण विकास पहलों को शामिल किया जाएगा, जो चयनित जिलों में कुल 10,00,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा।

स्रोत: *KRIBHCO द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

11. FISHCOPFED

मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत 1980 में स्थापित नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड (FISHCOPFED) भारत में मत्स्य

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देता है। कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित, FISHCOPFED मत्स्य मंत्रालय और NCDC सहित 104 सदस्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।

FISHCOPFED का मुख्य लक्ष्य मछुआरों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह पांच राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय और दिल्ली में दो खुदरा दुकानें संचालित करता है। इसकी संरचना में 22 राज्य स्तरीय संघ, 156 क्षेत्रीय संघ और 28,226 प्राथमिक समितियाँ शामिल हैं, जिनके 4 मिलियन से अधिक सदस्य हैं।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- गतिविधियों में 11 एक दिवसीय कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर (1), राज्य (3) और जिला स्तर (7) पर सेमिनार और कार्यशालाएं शामिल हैं, जो विभिन्न महीनों और स्थानों में आयोजित की जाएंगी।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लगभग 1,800 प्रतिभागियों को शामिल करना है और इनमें सहकारी शासन, युवा एवं महिला सशक्तिकरण, डिजिटल परिवर्तन तथा पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।
- इनमें नई दिल्ली में 300 प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार, तथा भुवनेश्वर, उज्जैन और कोलकाता में 200 प्रतिभागियों के साथ राज्य स्तरीय सेमिनार शामिल हैं।

स्रोत: *FISHCOPFED द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

12. अमूल

अमूल एक शीर्ष भारतीय डेयरी सहकारी समिती है। यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (GCMMF) के स्वामित्व वाला एक ब्रांड नाम है, जो गुजरात के 18 जिला दुग्ध संघों का एक शीर्ष निकाय है। AMUL का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। AMUL ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया है। AMUL भारत का सबसे बड़ा खाद्य ब्रांड है और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे विदेशी बाजारों में कदम रखा है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF), गुजरात का राज्य डेयरी संघ और अमूल के विपणन के लिए जिम्मेदार, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) मनाने के लिए गतिविधियों की योजना बनाएगा और उन्हें क्रियान्वित करेगा।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- 1 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की स्क्रीनिंग, साथ ही IYC लॉन्च कार्यक्रम, जिसमें पूर्ण पृष्ठ के समाचार पत्र विज्ञापन, अमूल सामयिक अभियान और अमूल वेबसाइट पर एक समर्पित IYC अनुभाग शामिल हैं।
- गुजरात के मोगर में डेयरी संयंत्र विस्तार का उद्घाटन और 18,600 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों में आईवाईसी दृश्यता सामग्री का शुभारंभ।
- गुजरात के खटराज में पनीर, यूएचटी और दूध प्रसंस्करण का विस्तार, प्रतिदिन 300 लाख सह-ब्रांडेड अमूल दूध पाउच का वितरण, और 200 शहरों में व्यवसाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन।
- गुजरात के 18,600 गांवों में विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में एक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन और वैश्विक एक्सपो में भागीदारी।
- हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी संयंत्र का विस्तार, स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं तथा गुजरात में 108 लाख से अधिक पेड़ लगाना।
- अमूल गुजरात के ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों में मासिक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिसमें हर महीने 4 लाख किसान शामिल होंगे।
- कुल प्रतिभागी: 12 करोड़ से अधिक

स्रोत: *AMUL द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

AIHFMCS

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति (AIHFMCS), जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, भारत में हथकरघा सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। इसका मिशन एक स्थायी विपणन मंच प्रदान करके, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ावा देकर और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करके हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाना है। AIHFMCS डिजाइन, रंगाई, बुनाई और विपणन में प्रशिक्षण प्रदान करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और सहायक नीतियों की वकालत करता है। यह शोरूम संचालित करता है, व्यापार मेलों में भाग लेता है, वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करता है और उत्पाद नवाचार का समर्थन करता है। इन प्रयासों के माध्यम से, AIHFMCS का उद्देश्य बुनकरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाते हुए भारतीय हथकरघा उत्पादों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करना है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- सभी हथकरघा शोरूमों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, सभी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा तथा सभी सहकारी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की योजना बनाई गई है। कोलकाता में दो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि हैदराबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर की हथकरघा प्रदर्शनियों और अन्य विशेष कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर के कारीगरों, खरीदारों और हितधारकों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित करना है ताकि अधिकतम भागीदारी हो सके।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बुनकरों को सशक्त बनाना, पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करना तथा हथकरघा क्षेत्र में सहकारी मॉडल के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है।

स्रोत: *AIHFMCS द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

14. NCDC

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC): कृषि उपज, खाद्य सामग्री, कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, लाख, साबुन, मिट्टी का तेल, कपड़ा, रबर आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, बढ़ावा देना और वित्तपोषण करना, उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और सहकारी समितियों के माध्यम से लघु वन उपज का संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात, इसके अलावा मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, हथकरघा आदि जैसी आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना और वित्तपोषण करना।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- आदर्श उपनियमों और जागरूकता अभियानों पर कार्यशालाएं चंडीगढ़, चेन्नई और गुवाहाटी सहित कई स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जिनमें शासन प्रथाओं और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़, पुणे, रांची, बेंगलुरु और गुवाहाटी जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों में "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण अभियान में प्रत्येक कार्यक्रम में 300 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- क्षमता विकास कार्यक्रमों में एनसीडीसी अधिकारियों, सहकारी सदस्यों, युवाओं और महिलाओं के लिए दिल्ली, भुवनेश्वर, जयपुर और गांधीनगर में प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मत्स्य व्यवसाय, सहकारी विपणन और भंडारण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सहकारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में लखनऊ और अन्य क्षेत्रीय मुख्यालयों में सहकारी नेताओं और अधिकारियों सहित 10,000 लोग भाग लेंगे, जिसमें शासन, टिकाऊ प्रथाओं और ज्ञान-साझाकरण पर जोर दिया जाएगा।

स्रोत: *NCDC द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

15. NCCF

देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाले संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) का उद्देश्य समग्र आर्थिक बेहतरी और वित्तीय स्वायत्तता के लिए आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता पर आधारित सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- एनसीसीएफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य सहकारी मंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य टीम सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें 50 से 100 व्यक्तियों की भागीदारी अपेक्षित है।
- ओडिशा में जागरूकता सत्र (100-150 प्रतिभागी) आयोजित किए जाएंगे, जबकि जनवरी से मार्च तक सात पूर्वोत्तर राज्यों में किसान संपर्क और बीज वितरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 700 किसान शामिल होंगे।

- जागरूकता अभियान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में कुंभ मेले का दौरा, जिसमें लगभग 50 से 75 प्रतिभागी शामिल होंगे।
- "आत्मनिर्भर कृषि" नामक एक राष्ट्रीय स्तर की पहल शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य कई स्थानों पर सुनिश्चित खरीद-वापसी कार्यक्रम के लिए किसानों का पंजीकरण करना है, जिसमें 500 से 700 प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है।
- पर्यावरणीय स्थिरता पर कार्यशालाएं (100-200 प्रतिभागी), वृक्षारोपण अभियान, तथा राष्ट्रीय स्तर पर हितधारक परामर्श (100 प्रतिभागी)।

स्रोत: *NCCF द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

16. NCHF

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ):- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) भारत में सहकारी आवास आंदोलन को बढ़ावा देता है और उसका समन्वय करता है। एनसीएचएफ का लक्ष्य सहकारी समितियों के माध्यम से सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- मासिक प्रकाशनों को एनसीएचएफ बुलेटिन और ई-न्यूजलेटर कोऑपरेटिव एंड हाउसिंग वॉयस में शामिल किया जाएगा, ताकि क्रमशः 2,000 और 1,200 से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचा जा सके।
- स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सहकारी आवास पर हैंडआउट्स भी वितरित किए गए। आवास सहकारी समितियों को बैनर और पोस्टर के माध्यम से आवास परियोजनाओं में पेड़ लगाने और जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- आवासन सहकारी समितियों के लिए जागरूकता अभियान और नेतृत्व विकास कार्यक्रम के साथ-साथ एनसीएचएफ, नई दिल्ली (60 प्रतिभागी) का अध्ययन दौरा आयोजित किया जाएगा।
- नई दिल्ली में सहकारी आवासन संघ के नेताओं पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिभागी होंगे।

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनसीएचएफ द्वारा बुलेटिन का एक विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, सहकारी सप्ताह के दौरान एक और विशेष अंक भी प्रकाशित किया जाएगा।

स्रोत: *NCHF द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

17. NCOL

मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसे NDDB, GCMMF-Amul, NAFED, NCCF और NCDC जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। NCOL PACS और FPO जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमाणीकरण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए संसाधन प्रदान करके जैविक खेती का समर्थन करता है। यह अप्रयुक्त जैविक समूहों की खोज भी करता है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है:

- कुंभ मेले के दौरान संचार में आईवाईसी(IYC) का लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 1,00,000 से अधिक उपस्थित लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सहकारी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) 2025 के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- आईवाईसी 2025 का लोगो भारत ऑर्गेनिक्स के 200 सफल आउटलेट्स पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगभग 60,000 उपभोक्ताओं को सहकारी लाभों के बारे में शिक्षित करना है।
- कर्मचारी सहभागिता माह के दौरान रिलायंस आउटलेट्स पर सहकारी मूल्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि स्थिरता माह के दौरान स्थायी सहकारी समितियों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, तथा 40 शहरों में ब्लिंकिट पर भारत ऑर्गेनिक्स के माध्यम से 16 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाएगा।
- नॉलेज शेयरिंग मंथ में केस स्टडी रिपोजिटरी और "लंच एंड लर्न" सीरीज शुरू की जाएगी, जिससे ज़ेप्टो पर भारत ऑर्गेनिक्स के ज़रिए 7.5 लाख ग्राहक जुड़ेंगे। नेटवर्किंग मंथ में सहकारी मेले और एमबीए इंटर्नशिप प्रोग्राम की सुविधा होगी, जिससे स्विगी पर भारत ऑर्गेनिक्स को 8 लाख ग्राहकों तक बढ़ावा मिलेगा।

- डिजिटल एंगेजमेंट मंथ #CooperativeImpact अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत अमेज़न पर भारत ऑर्गेनिक्स को 50 लाख उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा, पॉलिसी और एडवोकेसी मंथ में सहकारी समितियों के आर्थिक योगदान पर एक शोध पत्र पेश किया जाएगा, जिसमें फ्लिपकार्ट अभियान के तहत 50 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।
- वर्ष का समापन समापन माह के दौरान एक भव्य समारोह के साथ होगा, जिसमें वर्ष के अंत में प्रभाव रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर भारत ऑर्गेनिक्स अभियान शामिल होंगे, जिसमें कुल 1 करोड़ प्रतिभागी शामिल होंगे।

स्रोत: *NCOL द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

18. NCUI

1929 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) भारत के सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह सहकारी समितियों की वकालत करता है, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करता है। NCUI अपने राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (NCCE) के माध्यम से ICA, FAO और UNDP जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। यह कॉप कनेक्ट और CEDC जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। NCUI सहकारी समितियों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों को NCUI हाट और ई-हाट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाता है, जो "वोकल फॉर लोकल" पहल का समर्थन करता है। राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (NCRC) शिक्षा और शासन पर ध्यान केंद्रित करता है। NCUI की वैश्विक भागीदारी सहकारी आंदोलन में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। संगठन का नेतृत्व एक अध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी द्वारा किया जाता है।

कार्य योजना:

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 की निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है

- सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों को दूर करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी, जिसमें संघ, सोसाइटी और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, युवा सहभागिता पहलों में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताएँ शामिल होंगी।

- इस पहल का उद्देश्य स्थानीय सहकारी ढांचे को बढ़ाने और सामुदायिक विकास को समर्थन देने के लिए प्रत्येक उपखंड में 1,000 नई सहकारी समितियां और जूनियर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है।
- अभिनव सहकारी व्यवसाय विचारों का समर्थन करने के लिए एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें उनके योगदान के लिए शीर्ष प्रदर्शन कर्ताओं को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, सीईएएस पोर्टल का उपयोग डिजिटल क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसमें केस स्टडी और वीडियो के माध्यम से सफल सहकारी मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस योजना में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 50,000 सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देना और प्रमुख स्थानों पर स्थायी सहकारी स्टोर स्थापित करना शामिल है। राष्ट्रीय सम्मेलनों में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों और नीतिगत ढाँचों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें 500 से 1,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें कुल 50,000 प्रतिभागी भाग लेंगे।

स्रोत: *NCUI द्वारा प्रदान की गई कार्य योजना*

राष्ट्रीय संगठन

NABARD

1. राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान: डिजिटल प्रचार, टीवी/रेडियो विज्ञापन, समाचार पत्र अभियान, साक्षरता शिविर और YouTube पर प्रचार प्रसार

सामुदायिक कार्यक्रम:

2. युवा मैराथन और खेल: 500 से 1,000 प्रतिभागी।

3. स्वास्थ्य शिविर: 200 से 500 प्रतिभागी।

4. WSHG और JLG सभाएँ: 100 से 300 प्रतिभागी।

सहकारी सहभागिता गतिविधियाँ:

5. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ: ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर 100,000 से अधिक प्रतिभागी।

6. वाद-विवाद और विशेषज्ञ वार्ताएँ: 200 प्रतिभागी।

7. प्राकृतिक खेती और सहकारी कार्यक्रम: 20-30 प्रचार कार्यक्रम।

8. जिला-स्तरीय कार्यशालाएँ: 750 कार्यशालाएँ, प्रत्येक में 20-25 प्रतिभागी।

बैंक-स्तरीय कार्यक्रम:

9. पुरस्कार और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ: 100 प्रतिभागी।

10. वाद-विवाद और विशेषज्ञ वार्ता: 100 से 150 प्रतिभागी।

11. जमा संग्रहण शिविर: 200 से 500 प्रतिभागी।

राज्य स्तरीय सेमिनार:

12. सेमिनार और प्रदर्शनी: 1,000 से 3,000 प्रतिभागी।

13. TEDx-शैली COPx वार्ता: प्रत्येक राज्य में 500 प्रतिभागी।

14. राष्ट्रीय सहकारी ओलंपिक: दिल्ली में 5,000 से 10,000 प्रतिभागी।

15. सहकारी ट्रेन प्रदर्शनी: बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ देश भर में भ्रमण।

16. MoC के स्थापना दिवस (6 जुलाई, 2025) पर मेगा इवेंट: दिल्ली में 3,000 से 5,000 प्रतिभागी।

17. क्षेत्रीय IEC सामग्री: व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में वितरित की जाएगी।

NDDB

• ग्राम सहकारिता जागृति अभियान: 10,000 प्रतिभागियों के साथ 100 जिला स्तरीय कार्यक्रम, डेयरी किसानों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देंगे।

• सहकार से समृद्धि गोष्ठी कार्यक्रम: 5,000 प्रतिभागियों के साथ 20 राज्य स्तरीय कार्यक्रम, पुरस्कारों और मंत्री की उपस्थिति के साथ डेयरी सहकारी समितियों का जश्न मनाएंगे।

• सहकार से समृद्धि यात्रा उत्सव कारवां: प्रतियोगिताओं, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश भर में 10,000 प्रतिभागियों को शामिल करना।

• पॉडकास्ट श्रृंखला: 60,000 श्रोताओं तक पहुँचने वाले 12 एपिसोड, डेयरी सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

• श्वेत क्रांति 2.0 कार्यशालाएँ: 1,250 प्रतिभागियों के साथ 20 राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ।

• राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: सहकारी सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए 2025 में 240 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ छह राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम।

• सक्षम कार्यशालाएँ: सहकारी क्षेत्र में 400 महिला नेताओं को तैयार करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएँ।

• दुग्ध संघों और एफपीओ के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण: 40 कार्यक्रमों में 600 बोर्ड सदस्यों को शासन में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• एनडीडीबी हीरक जयंती: डेयरी सहकारी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 750 प्रतिभागियों के साथ जश्न मनाया जाएगा।

• कुल भागीदारी: सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए 88,240 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 204 कार्यक्रम।

NFDB

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी-2025) के लिए वार्षिक कार्य योजना और कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें भारत भर में मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शन यात्राओं की एक श्रृंखला शामिल है। पूरे वर्ष के दौरान, विभिन्न स्तरों पर 1,009 कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं- राष्ट्रीय, राज्य और जिला- कुल 293,100 प्रतिभागियों को लक्षित करते हुए। प्रमुख पहलों में प्रत्येक महीने 72 जिला-स्तरीय कार्यशालाएँ, सफल सहकारी समितियों के प्रदर्शन दौरे और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए राज्य-स्तरीय मत्स्य सहकारी मेले शामिल हैं।

21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग की विशेषता रखेंगे, जिसका समापन उत्कृष्ट मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए पुरस्कारों के रूप में होगा। एनएफडीबी सभी प्रचार सामग्री पर आईवाईसी-2025 लोगो और स्मारक डाक टिकटों के उपयोग के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा। डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आउटडोर ब्रांडिंग प्रयासों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के लिए एक व्यापक मीडिया योजना विकसित की गई है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी समितियों के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाना और पूरे वर्ष सहकारी पहलों में अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

NCCT

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान भारत भर के सहकारिता प्रबंधन संस्थानों (ICMs) द्वारा सहकारिता क्षेत्र में नवाचार, जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। एनसीसीटी सालभर मत्स्य, डेयरी और नवगठित एम-पैक्स के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहेगा, ताकि सहकारिता क्षेत्र की सतत प्रगति के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, लखनऊ

- **मार्च 2025:** "वैश्विक सहकारी विकास के रुझान" पर राष्ट्रीय वेबिनार
- **जुलाई 2025:** "सहकारिता का भविष्य: विजन 2050" पर राष्ट्रीय वेबिनार
- **सितंबर 2025:** "सहकारिता में युवा नेतृत्व और भागीदारी" पर राज्य कार्यशाला
- **नवंबर 2025:** "सहकारिता में चुनौतियाँ और अवसर" पर राज्य संगोष्ठी
- **कुल प्रतिभागी:** 600

2. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, जयपुर

- **मार्च 2025:** "समाज में सहकारिता की आवश्यकता" पर राज्य संगोष्ठी
- **अप्रैल 2025:** "सेवानिवृत्ति के मनोवैज्ञानिक प्रभाव" पर शिविर
- **जुलाई 2025:** "प्रेरणा और नेतृत्व" पर कार्यशाला
- **नवंबर 2025:** "मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन" पर संगोष्ठी
- **कुल प्रतिभागी:** 2,350

3. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, देहरादून

- **अप्रैल 2025:** "एसडीजी की ओर सहकारिता को गति देना" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **मई 2025:** "युवा सहकारी स्टार्टअप प्रबंधन" पर सेमिनार
- **जून 2025:** "सहकारी नीति और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र" पर सेमिनार
- **कुल प्रतिभागी:** 220

4. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, मदुरै

- **जुलाई-अक्टूबर 2025:** "सहकारिता एक बेहतर दुनिया बनाती है" पर पाँच जागरूकता कार्यक्रम
- **नवंबर 2025:** "सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" पर संगोष्ठी
- **कुल प्रतिभागी:** 665

5. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, चेन्नई

- **जून 2025:** "IYC-2025" पर ड्राइंग प्रतियोगिता
- **सितंबर 2025:** "सहकारी बैंक अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा" पर कार्यशाला
- **नवंबर 2025:** सहकारी सप्ताह समारोह
- **कुल प्रतिभागी:** 980।

6. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, इम्फाल

- **अप्रैल 2025:** सहकारी मेला और व्यापार एक्सपो
- **जुलाई 2025:** "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस" पर संगोष्ठी
- **दिसंबर 2025:** सहकारी व्यापार शो
- **कुल प्रतिभागी:** 2,750

7. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, कन्नूर

- **मई 2025:** सहकारी बैंक ग्राहकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- **जुलाई 2025:** सहकारी रोड शो और नाटक
- **दिसंबर 2025:** सहकारी समाज गठन पर प्रशिक्षण
- **कुल प्रतिभागी:** 3,840

8. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पुणे

- **अप्रैल 2025:** सफलता की कहानियों और निबंध प्रतियोगिता
- **सितंबर 2025:** "महिला सहकारी समितियों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाएं" पर संगोष्ठी
- **कुल प्रतिभागी:** 850 ,

9. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर

- **अक्टूबर 2025:** युवाओं के लिए सहकारी जागरूकता कार्यक्रम
- **दिसंबर 2025:** "नवाचार के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करना" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **कुल प्रतिभागी:** 760

10. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद

- **जून 2025:** शिक्षकों और संकायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- **जुलाई 2025:** सहकारी पोस्टर अभियान
- **नवंबर 2025:** PACS सचिवों के लिए केस स्टडी प्रतियोगिता
- **कुल प्रतिभागी:** 1,700

11. क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, चंडीगढ़

- **मई 2025:** "सहकारी विपणन रणनीतियाँ" पर संगोष्ठी
- **नवंबर 2025:** सहकारी सप्ताह समारोह
- **कुल प्रतिभागी:** 1,230

12. सहकारिता प्रबंधन संस्थान, तिरुवनंतपुरम

- **अप्रैल-दिसंबर 2025:** महिला सशक्तिकरण और एसडीजी पर कार्यशालाएँ और रैलियाँ
- **कुल प्रतिभागी:** 20,000

IFFCO
ICA

राज्यों की कार्य योजना

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान सहकारिता के निम्नलिखित बिंदुओं के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

इस दौरान सहकारिता की भावना का प्रचार, विस्तार और सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। सभी आयोजन प्राथमिक, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए आयोजित जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर पारदर्शिता, परिचालन दक्षता, नीतिगत सुधार। वहीं जिला स्तर पर पारदर्शिता, परिचालन दक्षता, नीतिगत सुधार। जबकि राज्य स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, नीतिगत सुधार, सहयोगात्मक तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी प्राथमिक समितियों में आदर्श उपविधियों का विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सभी सहकारी समितियों में मंत्रालय की पहलों पर विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाएगा। सहकारी संघों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार इस आयोजन के वित्त प्रबंधन हेतु भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डेयरी सहकारी समितियां/जिला दुग्ध संघ विस्तार (सदस्यों की संख्या) एवं वृद्धि (दुग्ध संग्रहण) की पंचवर्षीय योजना तैयार कर, उसे कार्यान्वियित किया जायेगा।

राज्य और जिला स्तर पर जैविक खेती, स्वच्छता अभियान और 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

अन्य माध्यमों के साथ ही, संसद टीवी के माध्यम से भी प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। फ्रांस, कोरिया, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में सहकारिता के श्रेष्ठ कार्यों का अध्ययन करने हेतु मंत्रालय द्वारा अध्ययन-दल भेजे जाएंगे। इसके साथ ही अफ्रीकी देशों, सेंट्रल एशिया के देशों और खाड़ी देशों से सहकारी संघों को भारत की सहकारी डेयरी उद्यम की प्रगति का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित कर, उनके प्रवास की व्यवस्था की जाएगी। अमूल एवं सभी सहकारी उत्पादों की पैकिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का 'लोगो' प्रदर्शित किया जाएगा। चार स्तरीय कार्य योजना–प्राथमिक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की तैयारियों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवनों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य आँकड़े:

- **देश में कुल सहकारी संस्थाएँ:** 8.2 लाख
- **कुल सदस्य:** 29.98 करोड़
- **क्षेत्र:** 30, जिसमें 'खादी और ग्राम उद्योग' क्षेत्र नया जोड़ा गया है

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की तैयारियों को लेकर विभिन्न राज्यों के एक्शन प्लान इस प्रकार से हैं:

असम

मुख्य आँकड़े: 11,152 सहकारी संस्थाएँ, 35.68 लाख सदस्य, महिला कल्याण क्षेत्र में अग्रणी (2,811 सहकारी संस्थाएँ, 4.89 लाख सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या - 20,18,375

गतिविधियां - 8

असम में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई हैं:

सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन असम के राज्यपाल द्वारा राजभवन में किया जाएगा, जिसमें राज्य स्तर पर 100 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए राज्य में सफल सहकारी आंदोलन की शपथ ली जाएगी।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- श्रीमंत शंकरदेव सभागार में "सहकारिता में सहकार" पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, साथ ही 30 PACS को POS मशीनें वितरित की जाएंगी।
- एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा, 10 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे।
- 100 PACS का E-PACS में परिवर्तित किया जाएगा।
- जूट उत्पादक क्षेत्रों के PACS के लिए असम सहकारी जूट मिलों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें 25 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- युवा सहकारी समितियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- RCS कार्यालय पोर्टल के कम्प्यूटरीकरण का शुभारंभ किया जाएगा।
- राज्य में सहकारिता वर्ष 2025 महिलाओं के लिए सहकारी समितियों पर केंद्रित होगा, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाली समितियों और उत्पादों को बढ़ावा देने के सहकारी मेला आयोजित किया जाएगा, साथ ही महिला समितियों के लिए प्रतियोगिताएं और गतिविधियां भी आयोजित किए जाएंगे।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहयोग, युवा जुड़ाव, पर्यावरण जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही असम के सहकारी क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना भी है।

अरुणाचल प्रदेश

मुख्य आँकड़े: 1,287 सहकारी संस्थाएँ, 54,150 सदस्य, बहुउद्देश्यीय क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति (531 सहकारी संस्थाएँ, 7,787 सदस्य)

अरुणाचल प्रदेश में IYC-2025 को मनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें राज्य, जिला और मिश्रित स्तरों पर सहयोग पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य समुदाय में जागरूकता, शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- सहकारी ध्वज फहराना और IYC-2025 के लिए स्मारक डाक टिकट का उपयोग करना।
- प्राथमिक सहकारी समितियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
- सहकारी उत्पाद एक्सपो, सहकार वार्ता और सहकारी इतिहास पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, जो राज्य दिवस के दौरान होगा।
- सहकारी विकास और विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई M-PACS (LAMPS, डेयरी, मत्स्य पालन) सहकारी समितियों के गठन पर कार्यशाला।
- 14 कम्प्यूटरीकृत लैम्प्स और 57 अन्य सहकारी समितियों, एपीसीसीएफ, मार्कफेड और एडब्ल्यूएफईडी के लिए कम्प्यूटरीकृत लेखांकन पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- दूध, मत्स्य पालन और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास योजनाओं पर अन्य राज्यों के संसाधन व्यक्तियों के साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण।
- सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से मंत्रालय के स्थापना दिवस को मनाने वाले कार्यक्रम।
- अरुणाचल प्रदेश सहकारी संघ (एपीएससीयू) के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ राष्ट्रीय सहकारी दिवस और राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम।
- डीआरसीएस के नेतृत्व में पांच क्षेत्रीय क्षेत्रों में दो दिनों के लिए राज्य भर की सभी समितियों के साथ सहकारिता शिविर।

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- राज्य सहकारी बैंकों द्वारा गतिविधियों और कार्यक्रमों का संचालन, एसएचजी के साथ ब्लॉक स्तर पर ऋण आउटरीच और वित्तीय साक्षरता शिविरों पर ध्यान केंद्रित करना।

- अरुणाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड द्वारा आयोजित एक्सपोजर यात्राएं, सफल संचालन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध सहकारी समितियों का दौरा करना।
- स्वर्ण जयंती के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सहकारी संघ (APSCU) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय सहकारी दिवस और सहकारी सप्ताह के लिए कार्यक्रम और समारोह।
- राज्य भर के कॉलेजों में सहकारी महोत्सव, जिसमें LAMPS सीमा बलों की भागीदारी के साथ प्रत्येक जिले में समारोहों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मिश्रित-स्तरीय गतिविधियाँ (राज्य और जिला)

- सहकारी विकास के लिए कार्यक्रम जो राज्य और जिला स्तर तक फैले हुए हैं, युवाओं, महिलाओं और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- प्रदर्शन यात्राओं और समारोहों के माध्यम से नवाचार और सीखने को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- शासन और समाज के सभी स्तरों पर सहकारी विकास, सदस्यता और जागरूकता बढ़ाने पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण प्रदान करना।

आंध्र प्रदेश

मुख्य आँकड़े: 17,824 सहकारी संस्थाएँ, 77.11 लाख सदस्य, PACS क्षेत्र में अग्रणी (2,048 सहकारी संस्थाएँ, 54.64 लाख सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान वर्ष भर चलने वाले जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी मूल्यों और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- किसानों के लिए सदस्यता और आधार सीडिंग अभियान।
- फोटो प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर और 2,000 जल स्टेशन।
- पुलों पर वृक्षारोपण (1,00,000 पेड़) और ग्रीन वॉल ब्रांडिंग।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और "दया की दीवार" पहल के लिए रैलियों का आयोजन ।
- स्कूलों और कॉलेजों में युवा जागरूकता अभियान और निबंध प्रतियोगिताएं।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- आईवाईसी-2025 कैलेंडर लॉन्च और पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण।

- एपीसीओबी और महिला सहकार योजना की आधारशिला।
- सहकारी ग्राम गोद लेने की योजना और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन।
- एपीसीओ प्रदर्शनियां, किसान एक्सपो और स्वच्छता दिवस।
- एपीसीओबी गठन दिवस और सहकारिता में महिलाओं की भूमिका के लिए समारोह।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

- सामाजिक न्याय दिवस जैसे वैश्विक दिवसों में भागीदारी।
- सोशल मीडिया अभियान (#IYC-AP)
- स्वतंत्रता दिवस पर युवा सहभागिता कार्यक्रम और शाक्तम प्रस्तुतियां।

<u>उत्तर प्रदेश</u>

मुख्य आँकड़े: 44,855 सहकारी संस्थाएँ, 1.93 करोड़ सदस्य, डेयरी (19,036 सहकारी संस्थाएँ, 7.87 लाख सदस्य) और PACS (7,684 सहकारी संस्थाएँ, 1.07 करोड़ सदस्य) क्षेत्रों में अग्रणी।

प्रतिभागियों की संख्या - 1,61,200

गतिविधियां - 20 से अधिक

मुख्यमंत्री द्वारा भव्य उद्घाटन, सहकारिता ध्वज फहराया गया, IYC-2025 लोगो लॉन्च किया गया-

- ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग के साथ डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, तथा 25,000 मीट्रिक टन गोदाम उद्घाटन और 15,000 मीट्रिक टन गोदाम की नींव के साथ बुनियादी अवसंरचना का विस्तार करना।
- 400 PACS में नए डेटा सेंटर, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का उद्घाटन किया गया
- मॉडल M-PACS विकसित किया गया तथा 15,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम शुरू किए गए।
- 100 मीट्रिक टन तथा 250 मीट्रिक टन गोदाम का उद्घाटन किया गया
- "सर्वश्रेष्ठ सहकारी गीत" प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया तथा 10,000 मीट्रिक टन गोदाम का उद्घाटन किया गया।
- "सहकार वाटिका" वृक्षारोपण अभियान के साथ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया
- सहकार सारथी योजना का शुभारंभ किया गया तथा 5,000 मीट्रिक टन गोदाम का उद्घाटन किया गया।

- युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए मेगा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है
- सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक (यूपीसीबी) की 15 नई शाखाएं खोलना।
- यूपीसीबी की नई वेबसाइट लॉन्च करना और यूपीएसडब्ल्यूसी द्वारा 20,000 मीट्रिक टन गोदाम का उद्घाटन करना।
- मेगा स्पोर्ट्स इवेंट, "हीरोज ऑफ़ कोऑपरेशन" कार्यक्रम और आईवाईसी-2025 के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन।

उत्तराखंड

मुख्य आँकड़े: 5,528 सहकारी संस्थाएँ, 16.77 लाख सदस्य, डेयरी क्षेत्र में प्रमुख (2,815 सहकारी संस्थाएँ, 1.42 लाख सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या - 6900 से अधिक

गतिविधियां - 10 से अधिक

उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- "उत्तराखंड में सहकारिता- भारत सरकार की पहल" पर राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन
- "सहकारी उत्पादों के लिए बाजार विस्तार" और "सहकारी समितियों के लिए दौड़" मैराथन पर राज्य स्तरीय पैनल, जिसमें सोशल मीडिया पर मजबूत कवरेज होगी।
- सहकारी सप्ताह के दौरान कार्यशालाओं, सेमिनारों की विशेषता वाले मेले का आयोजन

जिला-स्तरीय कार्यक्रम

- युवा सहकारी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
- सोशल मीडिया हैशटैग #StartWithCooperatives और #BuildingYouthCoopLeadership के साथ पहल को बढ़ावा देना।
- सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर एक सेमिनार का आयोजन
- महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन
- जिला स्तरीय नेतृत्व, सामूहिक सहकारी खेती जागरूकता और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण लाइव प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन

- वित्तीय साक्षरता कार्यशाला की मेजबानी
- महिला और युवा सशक्तीकरण, वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण अनुकूल कार्यशालाओं पर पैनल चर्चा
- समय समय पर सहकारी सदस्यों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
- स्कूलों और कॉलेजों में सहकारी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर "एक सतत भविष्य के लिए सहकारिता" पर एक निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन
- अगले वर्ष की गतिविधियों के लिए एक योजना सत्र और सहकारी पहलों के लिए एक ऑनलाइन फीडबैक सर्वेक्षण के साथ समापन करना।

ओडिशा

मुख्य आँकड़े: 7,581 सहकारी संस्थाएँ, 96.57 लाख सदस्य, PACS क्षेत्र में प्रमुख (4,259 सहकारी संस्थाएँ, 81.99 लाख सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या - 86,900

गतिविधियां - 343

ओडिशा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) मनाने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है-

- ओडिशा राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) के लिए एक महत्वाकांक्षी कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें 13 राज्य स्तरीय कार्यक्रम और 330 जिला स्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे नियोजित गतिविधियों की कुल संख्या 343 हो गई है।
- राज्य का लक्ष्य सेमिनार, अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान सहित विविध पहलों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा, ओडिशा मीडिया, लाइव-स्ट्रीमिंग और समुदाय-संचालित गतिविधियों का उपयोग करके आउटरीच को बढ़ाएगा।

जिला-स्तरीय कार्यक्रम

- राज्य के सभी 30 जिलों में सेमिनार और कार्यशालाएँ, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मैराथन और साइक्लेथॉन कार्यक्रम, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- सभी जिलों में सहकारी समितियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

- 60 जिला-स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रालय के स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जश्न।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला, रक्तदान शिविर,वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, मैराथन व साइक्लेथॉन कार्यक्रम और सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन।
- सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने के लिए दो राज्य स्तरीय कार्यक्रम।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

मुख्य आँकड़े: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह: 2,228 सहकारी संस्थाएँ, 1.35 लाख सदस्य, श्रमिक क्षेत्र (1,252 सहकारी संस्थाएँ, 38,287 सदस्य)

IYC 2025 योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और सतत विकास को आगे बढ़ाना है।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- सहकारी ध्वज फहराना, जागरूकता और सदस्यता अभियान शुरू करना।
- सहकारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन करना।
- भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए IYC कार्यक्रम विवरण का प्रसार करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और स्थापना दिवस मनाना।
- ग्रामीण विकास में ANSCB की भूमिका को मजबूत करना।
- सहकारी प्राथमिकताओं पर सम्मेलन आयोजित करना।
- कार्यक्रमों के साथ सहकारी सप्ताह मनाना।
- सफलता की कहानियों और नवाचारों का प्रदर्शन करना।
- स्थानीय सहकारी प्राथमिकताओं पर बैठकें आयोजित करना।
- नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक समितियों को बढ़ावा देना।
- ANSCB के माध्यम से माइक्रो ATM और रुपे क्रेडिट कार्ड वितरित करना।
- जिला स्तर पर प्रमुख सहकारी दिवस मनाना।
- जागरूकता कार्यक्रम और सफलता की कहानी प्रदर्शनी आयोजित करना।

ग्राम-स्तरीय गतिविधियाँ

- वृक्षारोपण और सहकारिता का विस्तार।
- समुदाय की भागीदारी के साथ प्रमुख सहकारिता दिवस मनाना।

- लक्षित गतिविधियों के माध्यम से गैर-लाभकारी PACS को मजबूत करना।
- ग्राम स्तर पर PACS के लाभों को प्रदर्शित करना।
- सहकारिता में युवाओं, महिलाओं और छात्रों को शामिल करना।
- राज्य, जिला, ग्राम-स्तर पर सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों का निर्माण करना।
- कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- मीडिया के माध्यम से IYC 2025 की जानकारी का प्रसार करना।

त्रिपुरा

मुख्य आँकड़े: 3,155 सहकारी संस्थाएँ, 5.30 लाख सदस्य, बहुउद्देश्यीय क्षेत्र में प्रमुख (604 सहकारी संस्थाएँ, 11,750 सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या - 9300

गतिविधियां - 24

त्रिपुरा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) मनाने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है-

- इन गतिविधियों का उद्देश्य सहकारी मूल्यों को बढ़ावा देना और राज्य भर में जन जागरूकता बढ़ाना है।
- व्यापक भागीदारी और प्रभावशाली जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए कुल 8 जिला-स्तरीय कार्यक्रम और 7 राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन।
- कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार के लिए वैन (प्रति जिला एक) सुविधा।
- सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन।
- जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
- जिला स्तर पर स्थापना दिवस पर सहकारी ध्वज फहराना।
- राज्य में अच्छी तरह से काम कर रही सहकारी समितियों के संपर्क दौरे की व्यवस्था करना।
- जिला स्तरीय कार्यशालाएं/सेमिनार (7 संख्याएं) का आयोजन।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन।
- त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा अगरतला में मछली महोत्सव का आयोजन।
- सहकारी समितियों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।
- हितधारकों और युवाओं को 'मंथन' सिनेमा दिखाया जाना।

- राज्य भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन।
- राज्य स्तर पर सहकारी सम्मेलन, जिसमें राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन।
- राज्य स्तरीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन।

कर्नाटक

मुख्य आँकड़े: 45,109 सहकारी संस्थाएँ और 2.46 करोड़ सदस्य। डेयरी (17,687 संस्थाएँ), PACS (6,196 संस्थाएँ), ऋण और बचत (5,211 संस्थाएँ), विविध गैर-ऋण (3,803 संस्थाएँ), बहुउद्देश्यीय (3,388 संस्थाएँ)

गतिविधियां - 8

कर्नाटक सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- साप्ताहिक पत्रिका "सहकार वार्ता" और फोटो प्रदर्शनी प्रकाशित करना।
- सहकारिता के उत्पादों के लिए मेले का आयोजन।
- राज्य सहकारी संघ अनूठी सहकारी समितियों पर लघु वीडियो फ़िल्म तैयार करना और उसका प्रसारण करना।

जिला-स्तरीय कार्यक्रम

- डीसीडीसी अपने जिलों के लिए अनूठी सहकारी उत्पाद प्रदर्शनी आयोजित करेगा।
- सहकारी समितियों में एससी/एसटी की भागीदारी बढ़ाने के लिए एससी/एसटी के नामांकन के लिए जिला स्तर पर अभियान।
- आईवाईसी 2025 के डाक टिकटों का वितरण।
- डीसीसीबी में पीएसीएस की गतिविधियों में विविधता लाने और पीएसीएस को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर कार्यक्रम
- सहकारी समितियों में सफलता की कहानियों का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम।
- "सहकार रत्न" पुरस्कार का वितरण।

केरल

मुख्य आँकड़े: 10,287 सहकारी संस्थाएँ, 3.59 करोड़ सदस्य, डेयरी क्षेत्र में अग्रणी (3,432 सहकारी संस्थाएँ, 12.38 लाख सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष (आईवाईसी) के लिए केरल कार्य योजना का उद्देश्य पूरे राज्य में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। विभिन्न पहलों,

आयोजनों और परियोजनाओं के माध्यम से, योजना आर्थिक विकास को बढ़ाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- केरल सहकारी समिति अधिनियम, नियमों और प्रक्रियाओं को कवर करने वाले सहकारी मैनुअल का प्रकाशन।
- विभागीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और कार्यान्वयन।
- अधिकारियों द्वारा सुव्यवस्थित और कुशल निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ।
- सहकारी एक्सपो 2025, जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने वाली प्रदर्शनी, बिक्री और सेमिनार शामिल हैं, और 'कॉपकेरल ब्रांडिंग' के तहत सहकारी उत्पादों का शुभारंभ।
- मातृ, नवजात और वृद्धावस्था देखभाल में कौशल विकास के लिए 'सखी योजना' का शुभारंभ।
- केरल भर में एलीट और लाइट कॉफी शॉप की स्थापना, जो एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है।
- रीकूप योजना का उद्देश्य व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और सहकारी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है।
- किसानों, सहकारी समितियों और जनता के बीच प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा के लिए अंगडी केरल ऐप का शुभारंभ।
- राज्य भर में संगोष्ठियों, अभियानों और प्रतियोगिताओं के साथ सहकारी सप्ताह का जश्न।
- केरल की बागवानी हब के रूप में स्थिति को बढ़ाने के लिए बागवानी विकास योजना, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और निर्यात को बढ़ावा देना।

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- सहकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली जिला स्तरीय संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ।
- 14 जिलों में केयर होम परियोजना के तहत बाढ़ पीड़ितों के लिए आवास परियोजनाएँ।
- धान की खरीद और प्रसंस्करण के लिए पलक्कड़ में एक आधुनिक चावल मिल की स्थापना।
- सहकारी एक्सपो से संबंधित स्थानीय सेमिनार और प्रचार कार्यक्रम।
- पहचाने गए स्थानों पर कंज्यूमरफेड के नेतृत्व में कॉफी की दुकानों की स्थापना।

राज्य और जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- सहकारी एक्सपो के लिए प्रचार कार्यक्रम और अभियान, राज्य और जिला दोनों स्तरों पर आयोजित किए गए।
- दोनों स्तरों पर कर्मचारियों और सहकारी सदस्यों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
- स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी उपलब्धियों और उनके प्रभाव को उजागर करने के लिए वार्षिक जागरूकता अभियान।

गोवा

मुख्य आँकड़े: 5,497 सहकारी संस्थाएँ, 15.61 लाख सदस्य, आवास क्षेत्र में प्रमुख (2,954 सहकारी संस्थाएँ, 80,152 सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या- 96,100

गतिविधियां - 22

गोवा सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

जिला और तहसील स्तरीय गतिविधियाँ

- जिले में लेखा, लेखा परीक्षा और कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों पर प्रशिक्षण।
- 40,000 प्रतिभागियों को लक्षित करते हुए ग्राम-स्तरीय सदस्यता अभियान का संचालन।
- नए एम-पैक्स, तहसील-स्तरीय पैक्स प्रशिक्षण और पैक्स प्रदर्शनियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन।
- अध्ययन यात्राओं और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों की व्यवस्था।
- सहकारी ध्वज फहराना, राष्ट्रीय सहकारी दिवस और मंत्रालय स्थापना दिवस मनाना।
- नुक्कड़ नाटकों, युवा सहकारी समितियों और सफलता की कहानियों के साथ राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह की मेजबानी।
- वृक्षारोपण अभियान, एम-पैक्स कम्प्यूटरीकरण और एफपीओ प्रदर्शनियों का आयोजन।
- नाबार्ड के सहयोग से किसानों के लिए ऋण और बीमा योजनाओं पर जागरूकता सत्र का आयोजन।

गुजरात

मुख्य आँकड़े: 83,495 सहकारी संस्थाएँ, 1.87 करोड़ सदस्य, आवास क्षेत्र में प्रमुख (30,599 सहकारी संस्थाएँ, 39.9 लाख सदस्य)

गुजरात सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- जिला स्तर पर "सहकारिताएँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं" थीम के साथ गणतंत्र दिवस परेड पर झांकी प्रस्तुति का आयोजन।
- डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए E-NAM जागरूकता के लिए किसान शिविर की मेजबानी करना।
- जिला दुग्ध संघ की महिला सदस्यों द्वारा प्रौद्योगिकी और उत्पादन सुधार पर जागरूकता के लिए दौरे आयोजित करना।
- शहर, तालुका और जिला स्तर पर केसीसी, माइक्रो एटीएम और पंजीकरण प्रमाणपत्रों का वितरण आयोजित करना।
- उपनियम संशोधन और कर्तव्यों, प्रबंधन और विनियमों पर समिति सदस्य प्रशिक्षण आयोजित करना।
- सहकारी समितियों में विभिन्न गतिविधियों, प्रौद्योगिकी और नई पहलों पर सदस्य सेमिनार आयोजित करना।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन करना।
- सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर पैनल चर्चाओं की मेजबानी करना।
- सहकारी विकास के समाधानों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष समाचार चैनलों और एफएम रेडियो पर टॉक शो आयोजित करना।

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- जिला स्तर पर सहकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन।
- वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला सहकारी समितियों में ऑडिट कैंप आयोजित करना।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकारी समिति की जानकारी प्रसारित करना।
- सहकारी सदस्यों के बीच जागरूकता के लिए दुग्ध संघों द्वारा 'डिजिटल रथ' का आयोजन करना।

- सहकारी भागीदारी को प्रेरित करने के लिए गाँव स्तर पर "मंथन फिल्म" का प्रदर्शन करना।
- कल्याणकारी उपायों के तहत मृतक सहकारी समिति के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को चेक वितरित करना।
- अप्रैल और अक्टूबर में PACS सदस्यता अभियान को बढ़ावा देना।
- सहकारी जागरूकता के लिए गाँव स्तर पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना।
- जिले में चीनी सहकारी समितियों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन सेमिनार आयोजित करना।
- जिले भर में सहकारी समितियों में शपथ और ध्वजारोहण गतिविधियाँ आयोजित करना।

गाँव स्तर की गतिविधियाँ

- "एक पेड़ माँ के नाम" (माँ के नाम पर एक पेड़) थीम के साथ सहकारी समितियों द्वारा वृक्षारोपण अभियान आयोजित करना।
- सहकारी समितियों में IYC-2025 समारोह के लिए दीवार पेंटिंग गतिविधियाँ आयोजित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टर प्रदर्शन और सूचना प्रसार के माध्यम से स्थानीय सहकारी गतिविधियों में सहकारी समितियों को शामिल करना।
- सहकारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के लाभों को प्रदर्शित करके सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करना।

राज्य, जिला, ग्राम गतिविधियाँ

- तालुका और जिला स्तरों पर कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी गतिविधियाँ आयोजित करना।
- कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर युवाओं, महिलाओं और छात्रों को सहकारी-संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए नगरपालिका एलईडी पर सहकारी गतिविधियों के लिए निःशुल्क प्रदर्शन स्थान प्रदान करना।
- क्षेत्र में स्कूलों और अस्पतालों का समर्थन करने के लिए धारा 70 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य निधि का उपयोग करना।
- स्थानीय समुदायों में सार्वजनिक सेवा पहलों को लागू करने के लिए सहकारी समितियों के साथ सहयोग करना।

चंडीगढ़

मुख्य आँकड़े: 476 सहकारी संस्थाएँ, 50,027 सदस्य, आवास क्षेत्र में प्रमुख (231 सहकारी संस्थाएँ, 19,487 सदस्य)

चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC) 2025 के लिए कार्य योजना का उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करके सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। इस व्यापक योजना में केंद्र शासित प्रदेश में सहयोग, सतत विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर की पहल शामिल हैं।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- आवास सहकारी समितियों में स्वच्छता अभियान, आवास क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने में सदस्यों को शामिल करना।
- आवास सहकारी समितियों के रखरखाव और मरम्मत जागरूकता पर संगोष्ठी, सहकारी आवास के प्रबंधन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना।
- सहकारिता मंत्रालय द्वारा नई पहलों पर संगोष्ठी, राष्ट्रीय स्तर की सहयोग नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
- आवास सहकारी समितियों की वार्षिक आम सभा बैठकें, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।
- सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन कार्यशालाएँ, सहकारी प्रबंधन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देना।
- सहकारी नीतियों और नवाचारों पर चर्चा, सहकारी मॉडलों में विकसित प्रवृत्तियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- राष्ट्रीय सहकारी दिवस और राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कारों के साथ उत्कृष्ट सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए।
- सहकारी ध्वजारोहण समारोह, IYC 2025 की उपलब्धियों पर चिंतन के साथ वर्ष के अंत को चिह्नित करता है।

जिला-स्तरीय गतिविधियाँ

- पड़ोसी राज्यों (पंजाब और हरियाणा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों का दौरा, सदस्यों को सफल सहकारी समितियों से सीखने का अवसर प्रदान करना।
- युवाओं के बीच सहकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से निबंध लेखन प्रतियोगिता।

- वन विभाग और किचन गार्डनिंग सहकारी समिति के समन्वय से वृक्षारोपण अभियान, सहकारी समितियों में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
- सहकारी महिला सम्मेलन, सहकारी समितियों में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- सहकारी समिति के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कार्यशालाएँ, जिसका उद्देश्य सदस्यों की सहभागिता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना है।
- सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिला-स्तरीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह समारोह।

मिश्रित-स्तरीय गतिविधियाँ (राज्य और जिला)

- **मीडिया योजना:** सभी आयोजनों के व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय और राज्य मीडिया को शामिल करें।
- **साल भर की गतिविधियाँ:** सहकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर आयोजन में सहकारी ध्वज फहराना और सहकारिता गीत।
- **युवा और महिला सहभागिता:** सहकारी गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित करने और शामिल करने के लिए विशेष पहल।
- वर्ष की सफलताओं को साझा करने और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए IYC 2025 गतिविधियों और सफलता की कहानियों की समीक्षा।

छत्तीसगढ़

मुख्य आँकड़े: 10,778 सहकारी संस्थाएँ, 52.1 लाख सदस्य, उपभोक्ता क्षेत्र में अग्रणी (3,160 सहकारी संस्थाएँ, 2.34 लाख सदस्य)

गुजरात सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- कार्यक्रम डिजाइन, मीडिया और प्रशिक्षण के लिए समितियों का गठन।
- प्रदर्शनी, सहकारी संगोष्ठियों और शासन कार्यशालाओं की मेजबानी करना।
- उच्च स्तरीय बैठकें, महिला एवं युवा सम्मेलन और सफलता की कहानी प्रकाशन आयोजित करना।
- राज्य महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कार्यक्रम और सम्मान कार्यक्रम आयोजित करना।

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- प्रदर्शनियों, पंजीकरण और प्रशिक्षण चर्चाओं की योजना बनाना।
- PACS पुनर्गठन, NCDC फंडिंग और सहकारी बैंकिंग पर चर्चा करना।
- सहकारी इतिहास सेमिनार, साइबर सुरक्षा कार्यशालाएँ और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।
- स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम और वित्तीय जागरूकता अभियान चलाना।
- सफल सहकारी समितियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करना।
- ब्लॉक स्तरीय गतिविधियाँ
- ड्रोन प्रदर्शन और PACS सदस्यता कार्यशालाओं की मेजबानी करना।
- जैविक उर्वरकों, फसल चक्र और सहकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण।
- सहकारी खेल आयोजन और वित्तीय सुरक्षा सत्र आयोजित करना।

बैंक स्तरीय गतिविधियाँ

- KCC वितरण सप्ताह, ऋण शिविर और वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ चलाना।
- साइबर सुरक्षा, KYC/AML अनुपालन और सहकारी बैंकिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रगतिशील किसानों और सहकारी योगदानकर्ताओं को सम्मानित करना।

ग्राम-स्तरीय गतिविधियाँ

- ग्राम सभाएँ, सदस्यता अभियान और सहकारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- नेतृत्व संदेशों के लिए वृक्षारोपण अभियान, नुक्कड़ नाटक और ग्राम सभाओं की मेज़बानी करना।
- वित्तीय समावेशन, PACS लाभ और FPO जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- PACS कम्प्यूटरीकरण और सहकारी विस्तार का समर्थन करना।

जम्मू और कश्मीर

मुख्य आँकड़े: 10,058 सहकारी संस्थाएँ, 4.84 लाख सदस्य, हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रमुख (4,013 सहकारी संस्थाएँ, 38,987 सदस्य)

गतिविधियां - 50 से अधिक

जम्मू और कश्मीर ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) मनाने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है-

- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।
- गतिविधियों में 5 UT-स्तरीय कार्यक्रम, 6 संभाग-स्तरीय कार्यक्रम और कई जिला-स्तरीय पहल शामिल हैं, जो सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारी समितियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी प्रासंगिकता को बढ़ावा देना है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- IYC-2025 को उजागर करने के लिए अगस्त में हर जिले में सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम, पौधारोपण अभियान और सहकार प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

संभाग स्तरीय कार्यक्रम

- सहकारी समितियों के उत्पादों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले सहकार मेलों का आयोजन।
- सहकारिता मैराथन/वॉकथॉन का आयोजन, महिला सहकार पहल, महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
- नाबार्ड के सहयोग से एफपीओ, सीईओ, बीओडी और महिला सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- पर्यटन और सूचना विभाग के सहयोग से सहकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले जागरूकता कार्यक्रम।
- प्रसार भारती/बिग एफएम/मिर्ची एफएम के सहयोग से सहकारी नेतृत्व शिखर सम्मेलन के साथ-साथ प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद कार्यक्रमों का आयोजन।
- जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में हितधारकों की बैठक के साथ यूएन आईवाईसी 2025 का शुभारंभ, जिसमें माननीय एलजी, सीएम और मंत्रियों सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।
- सभी सहकारी समिति कार्यालयों और जिलों को शामिल करते हुए पौधारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा।
- सहकारी समितियों (एफपीओ) के लिए स्थानीय सफलता की कहानियों और सहकार प्रदर्शनियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।
- ब्रांडिंग और जागरूकता: एक्सपोजर टूर और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले IYC-2025-ब्रांडेड लोगो और बैनर पहनेंगे।
- कई पहलों में नाबार्ड, पर्यटन, युवा सेवा, खेल और उच्च शिक्षा विभागों के साथ भागीदारी शामिल होगी, जिससे सभी क्षेत्रों में व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित होगा।

- यह समग्र योजना सहकारी समितियों के महत्व को उजागर करने, समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूटी जम्मू और कश्मीर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

झारखंड

मुख्य आँकड़े: 11,638 सहकारी संस्थाएँ, 20.6 लाख सदस्य, PACS क्षेत्र में प्रमुख (4,459 सहकारी संस्थाएँ, 13.39 लाख सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या- 35,585

गतिविधियां - 20 से अधिक

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए झारखंड सरकार की दो जिला स्तरीय कार्यशालाएं, एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण और लाह की खेती योजना है-

- राज्य सरकार सहकारी समिति के लिए त्रैमासिक बैठक भी करेगी
- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर 200 प्रतिभागियों के लिए सिधकोफेड, सदस्यता, सहकारिता और बाजार संपर्क पर दो कार्यशालाओं का आयोजन
- 200 प्रतिभागियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता और व्यवसाय विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- 500 प्रतिभागियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक, उत्पाद लॉन्च, आउटरीच, आईईसी गतिविधियां और प्रदर्शनी
- राज्य और जिला स्तर पर लाह किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों पर बीसीईओ/सीईओ और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण सत्र
- झारखंड में सहकारिता यात्रा पर संगोष्ठी।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- सभी जिलों में साइकिल रैली जिसमें 500 प्रतिभागी भाग लेंगे
- ब्लॉक स्तर पर सहकारिता पर चर्चा की जाएगी
- पंचायत स्तर पर सहकारी जागरूकता गोष्ठी/रैली का आयोजन
- स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन
- जिलों में वृक्षारोपण और सामुदायिक पहल
- वित्तीय साक्षरता, क्षमता निर्माण और सहकारी समितियों की बाधाओं पर चर्चा

तमिलनाडु

मुख्य आँकड़े: 22,245 सहकारी संस्थाएँ, 2 करोड़ सदस्य, डेयरी (9,707 सहकारी संस्थाएँ, 14.34 लाख सदस्य) और PACS (4,526 सहकारी संस्थाएँ, 1.13 करोड़ सदस्य) क्षेत्रों में प्रमुख।

प्रतिभागियों की संख्या- 3,07,475

तमिलनाडु राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) के अंतर्गत गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की योजना बनाई है।

- तमिलनाडु एक सुव्यवस्थित और विस्तृत कार्य योजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) मनाने के लिए कमर कस रहा है।
- राज्य 12 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और 7,980 जिला स्तरीय गतिविधियों की मेजबानी करेगा, जिसमें सहकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाएगा।
- ये कार्यक्रम सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, सहकारी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और समाज के सभी वर्गों में समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- गो ग्रीन ड्राइव, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, सदस्यता अभियान, खेल आयोजन और मैराथन, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, जैविक खेती सहकारी समितियों का गठन, सहकारी मेला एवं उत्सव, सामूहिक सफाई अभियान
- इमारतों की मरम्मत और रंग-रोगन के माध्यम से सहकारी समितियों के लिए नया रूप देना, ब्रांडिंग और छवि निर्माण के उपाय।
- सहकारी उत्पादों, हस्तशिल्प और सेवाओं का प्रदर्शन, श्रमिकों/सेवा सहकारी समितियों का निर्माण करना।
- सभी वर्गों को सहकारी दायरे में शामिल करने और पूंजी आधार बनाने के लिए खाता खोलने का अभियान।
- सहकारी परिवारों के लिए स्वास्थ्य जांच, नेत्र शिविर, रक्तदान अभियान तथा योग एवं कल्याण कार्यक्रम का आयोजन।
- ग्रामीण कारीगरों और नुक्कड़ नाटकों वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- नई पीढ़ी के सहकारी अभियान, कर्मचारियों और सदस्यों के बीच सहकारी सिद्धांतों की भावना का प्रचार प्रसार कार्यक्रम।

- अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों में नवाचार और प्रौद्योगिकी लाने के लिए सदस्यता अभियान का आयोजन।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राज्य स्तरीय बेटहकें, विभाग के कर्मचारियों और सहकारी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन, ।
- सहकारी मेला और उत्सव, स्वास्थ्य जांच, योग और रक्तदान अभियान सहित कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी समितियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना।

नागालैंड

मुख्य आँकड़े: 8,023 सहकारी संस्थाएँ और 3.06 लाख सदस्य। बहुउद्देश्यीय (2,204 संस्थाएँ), कृषि और संबद्ध (1,982 संस्थाएँ), PACS (1,172 संस्थाएँ), उपभोक्ता (803 संस्थाएँ), डेरी (758 संस्थाएँ) ।

प्रतिभागियों की संख्या- 13,494

गतिविधियां - 100

नागालैंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- ग्रामीण स्तर पर सहकारिता को बढ़ावा देने का कार्य
- राज्य स्तर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित करना
- शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सहकारिता की संभावनाओं पर सेमिनार आयोजित करना

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- सहकारी सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित
- विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वृक्षारोपण अभियान
- राजभवन में सहकारिता महोत्सव और दो डेयरी मेलों का आयोजन
- सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन
- प्रौद्योगिकी सुधार पर कार्यशाला का आयोजन
- सहकारी प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन
- सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम
- 17 जिलों में सहकारिता सप्ताह मनाने और राज्य की राजधानी में 3 दिवसीय सहकारी मेला का आयोजन ,

- PACS के लिए 17 जागरूकता सत्र, छात्रों के लिए 5 कार्यक्रम और सहकारिता गीत प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे।

पंजाब

मुख्य आँकड़े: 19,225 सहकारी संस्थाएँ, 30.66 लाख सदस्य, डेयरी क्षेत्र में प्रमुख (7,078 सहकारी संस्थाएँ, 2.61 लाख सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान वर्ष भर चलने वाले जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी मूल्यों और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।

- पंजाब ने आईवाईसी 2025 मनाने के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें सहकारी जागरूकता, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस पहल में महिलाओं, युवाओं और किसानों को शामिल करने के लिए 16 राज्य स्तरीय कार्यक्रम और कई जिला स्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे व्यापक प्रभाव सुनिश्चित होगा।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- पंजाब राज्य सहकारी बैंक: PACS में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (FLC) के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि पर 20 कार्यशालाएं/सेमिनार का आयोजन।
- PACS अध्यक्षों और समितियों के साथ संवादात्मक सत्र, सचिवों के लिए PACS कम्प्यूटरीकरण कार्यशालाएं।
- सहकारी बैंकिंग योजनाओं पर शाखा-स्तरीय ग्राहक बैठकें।
- महिला संयुक्त देयता समूहों के साथ सत्र, DCCB शाखाओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान।

शुगरफेड पंजाब और मिल्कफेड पंजाब

- नौ सहकारी चीनी मिलों में गन्ना जागरूकता शिविर।
- मिल्क यूनियन और एमपीसीएस स्तरों पर अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण प्रथाओं पर किसान प्रशिक्षण।
- डेयरी कर्मियों, दूध परीक्षकों और कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता और परिचालन प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

पंजाब राज्य कृषि विकास बैंक

- पीएडीबी और डीआरसीएस को शामिल करते हुए जिला-स्तरीय सभाएं और समारोह।
- नाबार्ड दिशानिर्देशों के तहत नियमित किसान क्लब की बैठकें।

राज्य-स्तरीय कार्यक्रम

- पंजाब राज्य सहकारी बैंक: पीएससीबी निदेशक मंडल के लिए अन्य राज्यों का एक्सपोजर दौरा, डीसीसीबी निदेशकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
- सीबीएस फिनेकल-10 उन्नयन समारोह, विशेषज्ञ व्याख्यान और पुरस्कार वितरण के साथ सहकारी सप्ताह समारोह का आयोजन।
- आईवाईसी 2025 गतिविधियों को समाप्त करने के लिए वर्ष के अंत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन।

शुगरफेड पंजाब

- परिष्कृत और फार्मा-ग्रेड चीनी का शुभारंभ, गुरदासपुर सीएसएम में नए चीनी संयंत्र का उद्घाटन, भोगपुर चीनी मिल में बायो-सीएनजी परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा।

मिल्कफेड पंजाब

- दूध संघों और एमपीसीएस के लिए गुणवत्ता और परिचालन प्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पंजाब राज्य कृषि विकास बैंक

- पीएडीबी सदस्यों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

साल भर की गतिविधियां

- ग्राम पंचायतों के साथ वृक्षारोपण अभियान।
- सहकारी सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले मीडिया अभियान।
- सभी कार्यक्रमों में सहकारिता गीत और ध्वजारोहण।
- युवाओं और महिलाओं की निरंतर भागीदारी की पहल।
- यह योजना सहकारी समितियों को मजबूत करने और IYC 2025 के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

मुख्य आँकड़े: 1,464 सहकारी संस्थाएँ और 3.3 लाख सदस्य। उपभोक्ता (575 संस्थाएँ), कृषि और संबद्ध (162 संस्थाएँ), डेरी (145 संस्थाएँ), बहुउद्देश्यीय (134 संस्थाएँ), PACS (96 संस्थाएँ)

प्रतिभागियों की संख्या- 1,56,308

गतिविधियां - 25 से अधिक

पुददुचेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- माहे परिवहन सहकारी समिति द्वारा माहे सहकारी केंद्र और नई बसों का उद्घाटन
- PONLAIT पंजीकरण दिवस मनाएं, हेलमेट जागरूकता, तथा जिलों में नए आइसक्रीम प्लांट की नींव रखना
- डेयरी सहकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन, तथा नई सहकारी सुविधाएं खोली जाएंगी
- हस्तकला प्रदर्शनी, कृषि के लिए ट्रैक्टर वितरण, तथा आवास भूखंडों का उद्घाटन करना
- मेगा मवेशी स्वास्थ्य शिविर की मेजबानी
- ऑडिट प्रक्रिया प्रशिक्षण आयोजित करें, तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन
- सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस के लिए मैराथन का आयोजन
- बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण, तथा पांडिचेरी सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन।
- वृक्षारोपण, ओणम उत्सव समारोह पर ध्यान केंद्रित करना
- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाएं, तथा नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण का आयोजन
- पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक की नई शाखा खोलने, कर्मचारी प्रशिक्षण आयोजित करने, तथा डेयरी कार्यक्रम का आयोजन

बिहार

मुख्य आँकड़े:_25,868 सहकारी संस्थाएँ, 1.61 करोड़ सदस्य, PACS क्षेत्र में प्रमुख (8,494 सहकारी संस्थाएँ, 1.36 करोड़ सदस्य)

बिहार में IYC 2025 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है-

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

राज्य सहकारिता विभाग और IPRD द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लॉन्च कार्यक्रम का उद्देश्य IYC 2025 और सहकारी आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

वित्तीय साक्षरता शिविर

- समग्र प्रगति का मूल्यांकन और चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर मध्यावधि समीक्षा की जाएगी।
- पटना में राज्य स्तरीय सहकारी मेला।
- युवा सहकारी समितियों पर केंद्रित राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलनआयोजित किए जाएंगे।
- महिला सहकारी समितियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
- बिहार राज्य के सहकारी आंदोलन और IYC 2025 पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेगा

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- बिहार के सभी 38 जिलों में आईईसी सामग्री (पोस्टर, ब्रोशर, पैम्फलेट) जारी किए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों, मूल्यों और शासन पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। हिंदी में सहकारी शासन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान जागरूकता के लिए सहकारी सदस्यों के लिए डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण (यूपीआई)।
- सहकारी समितियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना ।
- पूरे जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम और शासन और प्रबंधन प्रशिक्षण ।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- सहकारी समितियों पर जागरूकता कार्यक्रम।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन अभियान।
- प्रगति का आकलन करने के लिए मध्यावधि समीक्षा बैठकें।
- प्रभाव आकलन सर्वेक्षण।
- जिला स्तरीय सहकारी मेले।
- नीति वकालत अभियान और हितधारक परामर्श।
- सभी आईवाईसी 2025 गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को गहरा करना, नीतिगत बदलावों की वकालत करना और बिहार में सहकारी समितियों की स्थिरता और भविष्य के विकास को सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश

मुख्य आँकड़े: मध्य प्रदेश: 53,685 सहकारी संस्थाएँ, 1.09 करोड़ सदस्य, महिला कल्याण क्षेत्र में प्रमुख (11,775 सहकारी संस्थाएँ, 3.37 लाख सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या- 34,093

गतिविधियां - 11 से अधिक

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा IYC-2025 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है-

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- राज्यव्यापी स्वच्छता सप्ताह का आयोजन
- गणतंत्र दिवस समारोह में सहकार से समृद्धि पर झांकी का आयोजन
- मिशन कर्मयोगी: आईजीओटी पोर्टल पर अधिकारी विवरण अपलोड करने की सुविधा
- कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा और आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।
- जागरूकता के लिए कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- जिला स्तर पर 100 समितियों का पंजीकरण कराना।
- बैंकिंग गतिविधियों, टिकाऊ कृषि पर कार्यशाला
- फिशनेट वितरण, अनुदान और सदस्यता अभियान
- आवास संघ: आय सृजन के लिए औषधीय पौधों का रोपण।
- मछली सहकारी समितियों और एम-पैक्स और डेयरी सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास कार्यशाला का आयोजन।
- प्रजनक बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन।
- ऋण संरचना, टर्नअराउंड योजनाओं, साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित होगी
- नई मछली, डेयरी और एम-पैक्स सहकारी समितियों के लिए कार्यशाला का आयोजन।
- जबलपुर, नौगांव, इंदौर में एम-पैक्स और डेयरी सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नैनो उर्वरक और बीज वितरण पर कार्यशालाओं का आयोजन।
- पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का आयोजन।
- जिलों में डिजिटलीकरण कार्यशालाएं और स्वच्छता अभियान।
- सहकारिता पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।

महाराष्ट्र

मुख्य आँकड़े: 2,23,187 सहकारी संस्थाएँ, 8 करोड़ सदस्य, आवास (1,26,206 सहकारी संस्थाएँ, 1.90 करोड़ सदस्य) और PACS (21,186 सहकारी संस्थाएँ, 1.22 करोड़ सदस्य) क्षेत्रों में अग्रणी।

प्रतिभागियों की संख्या-53,200

गतिविधियां - 14

महाराष्ट्र राज्य द्वारा IYC-2025 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है-

- महाराष्ट्र राज्य जनवरी के महीने में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेगा।
- IYC 2025 के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में पूरे वर्ष उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुल 26 राष्ट्रीय स्तर और 26 राज्य स्तरीय कार्यक्रम या आयोजन की योजना बनाई गई है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- सहकारी आवास समितियों के हस्तांतरण विलेख और पुनर्विकास पर कार्यशाला का आयोजन।
- ऋण सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर कार्यशाला का आयोजन।
- आवास समिति शिखर सम्मेलन- समस्याएं और समाधान।
- VAMNICOM पुणे द्वारा DCCBs/UCBs के अधिकारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग, धोखाधड़ी रोकथाम और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम।
- मिलेट्स महोत्सव: आम महोत्सव का आयोजन।
- धनंजयराव गाडगिल ICM, नागपुर द्वारा मत्स्य समितियों के लिए प्रशिक्षण।
- वृक्षारोपण अभियान का आयोजन।
- सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस (6.7.2025) का वर्षगांठ समारोह।
- डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल आईसीएम, पुणे द्वारा युवा और महिला प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एसएचजी के लिए प्रशिक्षण।
- एम-पैक्स की व्यवसाय विकास योजना पर कार्यक्रम।
- केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियां।
- सहकारी महोत्सव; राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह समारोह।
- सहकार पुरस्कार - महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम का आयोजन।
- VAMNICOM पुणे द्वारा DCCB के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए शासन, अनुपालन, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्घाटन समारोह।
- ऋण सहकारी समितियों का सम्मेलन।

मणिपुर

मुख्य आँकड़े: 11,453 सहकारी संस्थाएँ, 8.22 लाख सदस्य, हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रमुख (5,632 सहकारी संस्थाएँ, 5.55 लाख सदस्य)

मणिपुर राज्य द्वारा IYC-2025 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है-

- "सहकारिताओं के बीच सहयोग" पहल की शुरूआत।
- दूरदराज के क्षेत्रों के लिए घर-घर जाकर बैंक खाता खोलने के लिए शिविर।
- PMMSY, FIDF और LIFIC पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम।
- सहकारिता से संबंधित विभिन्न पहलों पर जागरूकता कार्यक्रम।
- सहकारिता गीत और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सहकारिता की सफलता की कहानियों और युवा सहकारिताओं पर प्रकाश डालना।
- सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी।
- सहकारिताओं में सहकारिता की सफलता की कहानियों का आयोजन और युवा सहकारिताओं के बारे में जागरूकता और गठन।
- सहकारिता द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल और समकालीन फैशन की खूबसूरती को प्रदर्शित करते हुए हथकरघा और हस्तशिल्प पर फैशन शो।
- मंत्रालय के स्थापना दिवस के लिए चित्रकला प्रतियोगिता।
- जिलों और राज्यों में 20 स्किट प्रदर्शन।
- जिला स्तर पर 22 रोड शो और स्किट।
- सहकारिता ध्वज की मेजबानी और सहकारिता सप्ताह का जश्न।
- "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" पर प्रदर्शनी।

मेघालय

मुख्य आँकड़े: 3,081 सहकारी संस्थाएँ, 2.63 लाख सदस्य, बहुउद्देश्यीय क्षेत्र में प्रमुख (869 सहकारी संस्थाएँ, 25,792 सदस्य)

मेघालय सरकार IYC 2025 के दौरान सहकारी सिद्धांतों और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने और हितधारकों को जोड़ने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्य-स्तरीय और 49 जिला-स्तरीय कार्यक्रम पेश करेगी।

जिला-स्तरीय कार्यक्रम

- सहकारी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 7 ज़िलों में सेमिनार का आयोजन
- सभी जिलों में मैराथन, वृक्षारोपण अभियान, सहकारी सप्ताह और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह।
- जिला मुख्यालयों पर डिजिटल सेवा अभियान।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और सहकारिता मंत्रालय स्थापना दिवस के लिए समारोह।

राज्य-स्तरीय कार्यक्रम

- आईवाईसी-2025 गतिविधियों को शुरू करने के लिए वेबिनार और सेमिनार का आयोजन।
- राज्यव्यापी भागीदारी के लिए शिलांग मैराथन, सहकारी सदस्यों के लिए नेत्र स्वास्थ्य शिविर।
- सहकारी समितियों में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अभियान, वृक्षारोपण का प्रमुख अभियान।
- स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह का आयोजन।
- सहकारी पहलों को प्रदर्शित करने वाला राज्य-स्तरीय खाद्य महोत्सव।
- वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए क्रेडिट कैंप का आयोजन।
- सहकारी सप्ताह और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन। सहकारी नेताओं के लिए शैक्षिक दौरा और समापन बैठक।

मिजोरम

मुख्य आँकड़े: 1,273 सहकारी समितियाँ, 50,999 सदस्य, पशुपालन क्षेत्र में प्रमुख (290 सहकारी समितियाँ, 8,040 सदस्य)।

मिजोरम सरकार IYC-2025 के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

• IYC-2025 के लिए राज्य सर्वोच्च समिति (SAC) की स्थापना।

• IYC-राज्य सर्वोच्च समिति की पहली बैठक, उसके बाद राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की तीसरी बैठक।

• IYC-2025 समारोहों को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

• RCS के सचिव और अधिकारी सैतुअल जिले में प्राथमिक सहकारी समितियों का दौरा करेंगे

• प्रत्येक जिले में तीन समितियों को ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।

• थीम के अनुरूप वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

• IYC-2025 गतिविधियों के साथ निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए हर दो महीने में जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकें।

• जागरूकता के लिए IYC-2025 स्टिकर पूरे राज्य में वितरित किए जाएँगे।

• आयोजन को बढ़ावा देने के लिए एक ई-मीडिया टॉक शो प्रसारित किया जाएगा।

• सभी जिलों में एक रन/वॉक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

• राज्य और जिला दोनों स्तरों पर समाज के सदस्यों, नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

• कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहकारिता जागरूकता अभियान।

• IYC 2025 पर केंद्रित MOC स्थापना दिवस (6 जुलाई) पर मिजोरम विश्वविद्यालय (MZU) में विशेष कार्यक्रम

• सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आइजोल में युवा क्लबों और खेल आयोजनों को प्रायोजित करना।

• केरल, तमिलनाडु और गुजरात में सफल सहकारी समितियों का अध्ययन दौरा।

• राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (नवंबर का पहला शनिवार) और राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह (14-20 नवंबर) मनाना।

• राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम, जिसमें वनपा हॉल, आइजोल में उद्घाटन और समापन समारोह शामिल हैं।

• सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
द्वारा

नाबार्ड
42
स्थापना दिवस
12 जुलाई 2023
नई दिल्ली
RuPay
Kisan credit card

राजस्थान

मुख्य आँकड़े: कुल 40,679 सहकारी संस्थाएँ, 90,05,464 सदस्य, डेयरी क्षेत्र में प्रमुख (18,140 समितियां और 5,17,604 सदस्य), जबकि PACS क्षेत्र में 8,386 समितियां और 64,30,902 सदस्य हैं।

आईवाईसी 2025 योजना का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करना है।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- आईवाईसी-2025 का उद्घाटन और सहकारी आंदोलन पर सम्मेलन।
- शहरी सहकारी बैंकों पर कार्यशाला।
- एनसीडी, एनसीसीई, नेफेड पोर्टल पर सहकारी समितियों को शामिल करना।
- सदस्यता और जागरूकता अभियान।
- "म्हारो खातो म्हारो बैंक" पर संगोष्ठी और अभियान।
- आरसीडीएफ, अपेक्स बैंक और डीसीसीबी के साथ कार्यशालाएँ।
- सहकार मेला और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- PACS (GSS) का सुदृढ़ीकरण और भंडारण गोदाम का उद्घाटन।
- सहकार गैलरी का उद्घाटन।
- एमओसी स्थापना दिवस और सहकारिता दिवस समारोह।
- M-PACS (सीएससी, पीएमकेएसके, कस्टम हायरिंग) को मजबूत करने पर कार्यशाला।
- वृक्षारोपण और वित्तीय साक्षरता शिविर।
- एफपीओ उत्पादों की प्रदर्शनी।
- दीपावली मेला और सहकारी उत्सव सप्ताह।
- सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण सह एक्सपोजर विजिट।
- पुरस्कार वितरण और समापन समारोह IYC-2025।

जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- सदस्यता और जागरूकता अभियान (41 जिले) ।
- महिला GSS और समितियों के परिसमापन पर कार्यशालाएँ।
- NCOS, NCEL और BBSL पर संगोष्ठी।
- "म्हारो खातो म्हारो बैंक" अभियान।
- PACS (GSS) को मजबूत करना।
- वृक्षारोपण और वित्तीय साक्षरता शिविर।

- FPO उत्पादों की प्रदर्शनी।
- सहकार मेला और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- MOC स्थापना दिवस और सहकारिता दिवस का उत्सव।

राज्य, जिला, गाँव की गतिविधियाँ

- नवनिर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदाम का उद्घाटन (राज्य और जिला)
- सहकार गैलरी का उद्घाटन (राज्य) ।
- RCDF, अपेक्स बैंक और DCCBs (राज्य और जिला) के साथ कार्यशालाएँ।
- M-PACS (CSC, PMKSK, कस्टम हायरिंग) को मजबूत करने पर कार्यशाला (जिला और राज्य) ।
- "म्हारो खातो म्हारो बैंक" अभियान (राज्य और जिला) ।
- दीपावली मेला और सहकारी महोत्सव सप्ताह (राज्य और जिला) ।
- सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण सह प्रदर्शन दौरा (गुजरात/केरल/महाराष्ट्र) ।
- आईवाईसी-2025 का पुरस्कार वितरण और समापन समारोह (राज्य) ।

सिक्किम

मुख्य आँकड़े: 3,803 सहकारी संस्थाएँ, 1.13 लाख सदस्य, श्रमिक क्षेत्र में प्रमुख (2,757 सहकारी संस्थाएँ, 33,383 सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) 2025 के लिए सिक्किम की कार्ययोजना जागरूकता, प्रशिक्षण, प्रचार, सहयोग और प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और छात्रों को शामिल किया जाएगा।

जिला स्तरीय कार्यक्रम

- एफपीओ गतिविधियां: जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ध्वजारोहण और एफपीओ उत्पादों पर आईवाईसी लोगो को शामिल करना।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

- सहकारी उत्पादों और सरकारी फ़ाइल बोर्डों पर आईवाईसी 2025 लोगो।
- बोर्ड की बैठकें उप-नियमों के अनुसार आयोजित की जायेंगी।
- मीडिया योजना के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ सहयोग।
- महिलाओं, युवाओं, छात्रों और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को लक्षित करते हुए अंतर-विभागीय सहयोग।

- मासिक पीआईबी सूचना प्रसार, प्रचार के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का उपयोग।
- वेबसाइट अपडेट और आईवाईसी लोगो के साथ वाहन स्टिकर लगाना अनिवार्य।
- मीडिया पार्टनर की पहचान, एक्स अकाउंट सक्रियण और प्रभावशाली लोगों और पॉडकास्ट कार्यक्रम।

राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी

- आईवाईसी टेम्पलेट में उल्लिखित राष्ट्रव्यापी गतिविधियों में भागीदारी।

लद्दाख

मुख्य आँकड़े: लद्दाख: 271 सहकारी संस्थाएँ, 31,150 सदस्य, PACS क्षेत्र में प्रमुख (160 सहकारी संस्थाएँ, 16,221 सदस्य)

लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- सहकारी विकास के लिए जिला, राज्य और शीर्ष स्तरीय समितियों का गठन।
- लेह और कारगिल दोनों जिलों में जैविक खेती अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सहकारी समितियों के प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और व्यापार करने में आसानी पर कार्यशालाओं का आयोजन।
- सहकारी प्रबंधन और प्रशासन पर प्रशिक्षण के लिए एनसीयूआई के साथ सहयोग।
- विशेष अभियान गैर-कार्यात्मक सहकारी समितियों को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- युवाओं और महिलाओं को जागरूकता अभियान, विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर के कार्यक्रमों से जोड़ना।
- सहकारी इतिहास पर सहकारी उत्सव और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन।
- फल उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा खुबानी की तुड़ाई, प्रसंस्करण और विपणन की विशेषता वाले कार्यक्रम।
- लेह और कारगिल दोनों में कम्प्यूटरीकृत PACS के लिए प्रशिक्षण।
- मछली पालन, दूध खरीद और पश्मीना विपणन पर कार्यशालाएं।
- संबंधित विभागों के सहयोग से कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन।
- राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और मंत्रालय का स्थापना दिवस मनाना।
- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और कैफेटेरिया सहित विभागीय परिसंपत्तियों का उद्घाटन।

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अनुरूप सहकारी विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन करना।

लक्षद्वीप

मुख्य आँकड़े: 42 सहकारी संस्थाएँ, 84,901 सदस्य, विपणन क्षेत्र में प्रमुख (10 सहकारी संस्थाएँ, 62,833 सदस्य)

प्रतिभागियों की संख्या- 400 से अधिक

गतिविधियां- 8

लक्षद्वीप सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- लक्षद्वीप सरकार किल्टन द्वीप पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ क्रेडिट सोसायटी/पैक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ (सहकार-से-समृद्धि कार्यक्रम) करेगी।
- एम-पैक्स मछुआरा सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करेगी
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए जागरूकता और क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन।
- युवा जुड़ाव पर केंद्रित सेमिनार और क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन।
- कवरत्ती द्वीप पर सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस का जश्न।
- 10 द्वीपों में स्कूली छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- आईसीएम में निदेशक मंडल, सोसायटी कर्मचारियों और सहकारी विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- 10 द्वीपों में सहकारी सप्ताह समारोह का आयोजन।
- 30 प्रतिभागियों के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन दौरा।

हरियाणा

मुख्य आँकड़े: 33,254 सहकारी संस्थाएँ, 49.93 लाख सदस्य, श्रमिक क्षेत्र में अग्रणी (10,266 सहकारी संस्थाएँ, 1.35 लाख सदस्य)

गतिविधियां - 18 से अधिक

हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित कार्य कर रही है-

- आईवाईसी-राज्य शीर्ष समिति, वार्षिक कैलेंडर, आईवाईसी लोगो प्रचार, स्वच्छता अभियान, गणतंत्र दिवस की झांकी, सहकारी पॉडकास्ट और ई-ऑफिस कार्यान्वयन का शुभारंभ।
- सदस्यता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियां, उत्सव और प्रचार अभियान का आयोजन।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों के साथ "सहकारिता में महिलाओं को सशक्त बनाना"।
- "सहकारिता में युवा भागीदारी" पर जोर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निबंध प्रतियोगिताएं, कौशल विकास कार्यक्रम और मैराथन का आयोजन।
- विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, ई-वाहन वित्तीय योजनाएं और आपदा प्रबंधन अभ्यास।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, वृक्षारोपण अभियान और सहकारी समितियों के लिए ऐतिहासिक पर्यटन के साथ "सहकारिता की विरासत और परम्परा" का जश्न मानना।
- स्वतंत्रता दिवस पर जिंगल्स, ध्वज वितरण और सहकारिता पर वेबिनार के माध्यम से "देशभक्ति और सहकारिता" को बढ़ावा।
- ज्ञान विनिमय कार्यक्रमों, हाशिए पर पड़े समूहों के सशक्तिकरण पर कार्यशालाओं और वेबिनार के माध्यम से "सहकारिता में समावेशिता" पर ध्यान केंद्रित करना।
- सहकारी समितियों के लिए पुस्तक वाचन, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से "सहकारी शिक्षा को मजबूत बनाने" पर जोर देना।
- सहकारिता दिवस समारोह, पुरस्कार समारोह और समूह आवास समितियों पर कार्यशालाओं के माध्यम से "सहयोग और एकता" पर प्रकाश डालना।
- समापन समारोह, आईवाईसी 2025 रिपोर्ट विमोचन और हरियाणा सहकारी प्रकाश के विशेष संस्करण के साथ "मान्यता और भविष्य की दृष्टि" को चिह्नित करना आदि।

हिमाचल प्रदेश

मुख्य आँकड़े: 5,402 सहकारी संस्थाएँ, 17.68 लाख सदस्य, PACS क्षेत्र में प्रमुख (2,254 सहकारी संस्थाएँ, 13.74 लाख सदस्य)

गतिविधियां - 22

हिमाचल प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) मनाने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है-

- हिमाचल प्रदेश राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC-2025) के अंतर्गत गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की योजना बनाई है।
- इन पहलों में सामुदायिक सेवा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा जुड़ाव और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सम्मेलन शामिल हैं।
- कुल 17 जिला/मंडल-स्तरीय गतिविधियाँ और 13 राज्य-स्तरीय गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं, साथ ही हिमकोफेड, मिल्कफेड और अन्य जैसे राज्य-स्तरीय संघों द्वारा आयोजित गतिविधियाँ भी प्रस्तावित की गई हैं।

जिला/मंडल स्तरीय गतिविधियाँ

- सफाई अभियान और वृक्षारोपण सहित सामुदायिक सेवा पहल।
- सदस्यों और प्रबंध समितियों के लिए जागरूकता शिविर।
- विशिष्ट प्रभागों और जिलों को कवर करने वाले क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन।
- कांगड़ा डिवीजन: कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा।
- शिमला डिवीजन: शिमला, सिरमौर, किन्नौर और सोलन।
- मंडी डिवीजन: लाहौल और स्पीति, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर।
- डीसीसीबी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन।
- सहकारी समितियों के लिए डिजिटल उपकरणों पर प्रशिक्षण।
- सहकारी खेती की तकनीक और प्राकृतिक/जैविक खेती पर प्रशिक्षण।
- स्कूलों और कॉलेजों में युवा जागरूकता शिविर का आयोजन ।
- वृक्षारोपण अभियान सहित पर्यावरण जागरूकता अभियान।
- स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का आयोजन।
- सहकारी समितियों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन।
- सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता पर कार्यशालाओं का आयोजन।
- विशेष लेखा परीक्षा अभियान, सहकारी उद्यमिता प्रशिक्षण, शीतकालीन वस्त्र और खाद्य मेले का आयोजन।

राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

- पहले और दूसरे क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन।
- शिमला में सहकारी मैराथन का आयोजन।
- सहकारी समितियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहकारी बैंकिंग/ऋण में नवाचारों पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी।
- पहले राज्य स्तरीय सहकारी खेल महोत्सव का आयोजन ।
- सहकारी व्यवसाय मॉडल और युवा जुड़ाव पर कार्यशालाएँ।

- सहकारी समितियों के लिए डिजिटल उपकरणों पर प्रशिक्षण।

राज्य स्तरीय संघों द्वारा गतिविधियाँ

राज्य स्तरीय संघ जैसे कि हिमकोफेड, मिल्कफेड, वूलफेड और हिमफेड पूरे वर्ष अतिरिक्त गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। ये संघ रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन्हें मासिक या त्रैमासिक आधार पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को प्रस्तुत करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए मीडिया प्लान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में सहकारिताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आईवाईसी के लिए मीडिया योजना में सहकारिता के मूल मूल्यों को बढ़ावा देने, वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सहकारी आंदोलनों में भागीदारी और विकास को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

2025 में, सहकारिता मंत्रालय और इसके संघों द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिन्हें कई मीडिया चैनलों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। प्रत्येक महीने, प्रमुख गतिविधियों को राष्ट्रीय (अंग्रेजी और हिंदी) और क्षेत्रीय मीडिया दोनों में प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सोशल मीडिया टीमें, सहकारिता मंत्रालय के समन्वय में, चर्चा का विषय बनेंगी, जबकि डीडी और एआईआर को लाइव कवरेज और प्रोग्रामिंग के लिए लगाया जाएगा।

उल्लेखनीय कार्यक्रमों में जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) समारोह का शुभारंभ, मार्च में एनसीसीएफ का प्लेटिनम जुबली समारोह और जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और एनडीडीबी के स्थापना दिवस का स्मरणोत्सव शामिल होगा। अतिरिक्त कार्यक्रमों में अक्टूबर में नैफेड की 67वीं वर्षगांठ, नवंबर में इफको का स्थापना दिवस और दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के समापन समारोह जैसे मील के पत्थर मनाए जाएंगे। सहकारिता आंदोलन को और बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्री और क्षेत्रीय नेताओं जैसे प्रमुख हस्तियों के लेख प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है।

1. मीडिया प्लान का उद्देश्य

<u>अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए मीडिया योजना का प्राथमिक उद्देश्य है:</u>

जागरूकता को बढ़ावा देना: वैश्विक दर्शकों को सहकारी समितियों के लाभों और टिकाऊ और लचीले समुदायों के निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना।

भागीदारी को प्रोत्साहित करना: व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को सहकारी समितियों का समर्थन करने और उन्हें बनाने के लिए प्रेरित करना।

सहकारिता के प्रभाव का जश्न मनाना: दुनिया भर में सहकारी संगठनों की उपलब्धियों को उजागर करना।

सहकारी आंदोलन को मजबूत करना: सहकारी समितियों की दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाना, समावेशी आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर जोर देना।

2. लक्षित दर्शक

• प्राथमिक दर्शक

- वैश्विक युवा, उद्यमी और छोटे व्यवसाय।
- सरकारें, नीति निर्माता और विकास संगठन।
- कृषि, वित्त, आवास, खुदरा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ एवं उनके सदस्य ।

• द्वितीयक दर्शक

- सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षाविद, शोधकर्ता और संस्थान।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन।
- मीडिया आउटलेट, प्रभावशाली व्यक्ति और सोशल मीडिया समुदाय।

3. मीडिया चैनल

व्यापक पहुँच और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए, मीडिया योजना को बहु-चैनल दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए-

प्रिंट मीडिया:

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान स्थानीय रूप से केंद्रित प्रचार और प्रचार सामग्री (ब्रॉशर, पैम्फलेट्स) का प्रकाशन किया जाएगा।
- पूरे महीने में आयोजित गतिविधियों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मासिक बुलेटिन जारी किए जाएंगे।
- अमूल और अन्य सहकारी उत्पादों की पैकिंग पर IYC-2025 का 'लोगो' प्रदर्शित किया जाएगा।
- विशेषज्ञों द्वारा संपादकीय लेख प्रकाशित किए जाएंगे।
- सभी स्तरों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रकाशन किया जाएगा।

सोशल मीडिया:

- आधिकारिक हैंडल्स के माध्यम से समय-समय पर जानकारी के प्रसार के लिए ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया (SMS, WhatsApp, Email, वेबसाइट, Facebook, Twitter, Instagram आदि) का विशेष इस्तेमाल किया जाएगा।
- हर महीने ट्विटर पर हैशटैग्स एवं पोल के साथ ट्रेंडिंग किया जाएगा।
- सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर जानकारी के प्रसार के लिए चैटबॉट का उपयोग भी किया जाएगा।
- सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों के वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे।
- इन्फ्लुएंसर्स/पॉडकास्ट की सक्रिय भागीदारी भी शामिल की जाएगी।
- सहकारिता से जुड़े विषयों को प्रमुख वेब सीरीज मे शामिल करवाया जाएगा।
- सभी स्तरों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

वेबसाइट और ब्लॉग:

- संसाधनों, इवेंट विवरण और केस स्टडी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए एक समर्पित अनुभाग या माइक्रोसाइट बनाएं।
- लेख और सफलता की कहानियाँ प्रकाशित करें जो दिखाते हैं कि कैसे सहकारिताएँ गरीबी, बेरोज़गारी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रही हैं।

ईमेल अभियान:

- सहकारी आयोजनों, पहलों और अवसरों के बारे में वैश्विक हितधारकों को समाचार पत्र भेजें।

पारंपरिक मीडिया:

- प्रिंट मीडिया: विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा) में सहकारी समितियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विशेष लेख।
- टेलीविज़न और रेडियो: जागरूकता बढ़ाने के लिए टीवी और रेडियो कार्यक्रमों, साक्षात्कारों और वृत्तचित्रों का उपयोग करें। सहकारी समितियों के महत्व और आर्थिक और सामाजिक विकास में उनके योगदान पर विशेष खंड।

इवेंट और सक्रियताएँ:

- **वैश्विक सम्मेलन और वेबिनार:** सहकारी समितियों के लाभों पर वेबिनार, पैनल चर्चा और सम्मेलनों का आयोजन करें या उनमें भाग लें। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, सहकारी नेताओं और नीति निर्माताओं को आमंत्रित करें।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस (जुलाई का पहला शनिवार):** इस दिन का उपयोग वैश्विक समारोहों, विशेष प्रसारणों और आउटरीच अभियानों के लिए करें।
- **कार्यशालाएँ और स्थानीय सक्रियताएँ:** सहकारी समितियों के बारे में ज्ञान फैलाने के लिए समुदायों, व्यवसायों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय कार्यशालाएँ आयोजित करें।

आउटडोर विज्ञापन:

- **बिलबोर्ड और पोस्टर:** प्रमुख शहरों, विश्वविद्यालय परिसरों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों में विज्ञापन लगाएं जो सहकारी समितियों के महत्व को उजागर करते हैं।
- **सार्वजनिक परिवहन अभियान:** बड़े पैमाने पर सहकारी जागरूकता अभियानों के लिए शहरी क्षेत्रों में बसों, ट्रेनों और मेट्रो का उपयोग।
  मीडिया प्रयासों से पूरे वर्ष विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से लाइव प्रसारण, ऑप-एड योगदान और केंद्रित आउटरीच के साथ व्यापक कवरेज और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

''एक पेड़ मां के नाम'' - वृक्षारोपण अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर **'एक पेड़ मां के नाम'** अभियान की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण की जिम्मेदारी को माताओं के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ जोड़ने वाली एक अनूठी पहल है। इस अभियान के तहत देशभर में करीब **140 करोड़ पेड़** लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और पिछले एक दशक में वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत की प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के सतत विकास की खोज के साथ जुड़ा हुआ है!

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सितंबर 2024 तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय समय सीमा से 5 दिन पहले ही 25 सितंबर 2024 को वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हासिल कर लिया था।

सहकारिता मंत्रालय ने भी **'एक पेड़ मां के नाम'** अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों, फेडरेशनों, सहकारी समितियों और हितधारकों को देशभर में करोड़ों पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी संस्थाओं ने बड़ी संख्या में पौधारोपण कर इस अभियान को एक विशाल रूप देने की पहल शुरू कर दी है।

इस पहल का उद्देश्य जीवन को पोषित करने में माताओं की भूमिका का सम्मान करना और पर्यावरण को बचाना है। मां की तरह पेड़ न केवल हमारे जीवन को बचाए रखते हैं,

बल्कि अगली पीढ़ी के लिए पोषण, सुरक्षा और भविष्य भी प्रदान करते हैं। इस पहल के माध्यम से प्रतिभागी अपनी माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाकर एक स्थायी स्मृति बना सकते हैं।

वर्षांत पर कार्यवाही

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बाद की गतिविधियों पर कार्ययोजना:

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (IYC-2025) के उत्सव के उपरांत, सहकारी क्षेत्र की सफलता, अनुभव और प्रभाव का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं:

मूल्यांकन रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण:

- IYC-2025 के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों और पहलों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- इन कार्यक्रमों की सफलता, प्रभाव और अनुभव का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

विशेष रिपोर्ट तैयार करना:

- सहकारी संस्थाओं, PACS, दुग्ध संघ, बैंकों और सहकारी संघों द्वारा एक वर्ष में की गई प्रगति और उपलब्धियों पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

नीतिगत और कानूनी सुझाव:

- सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत और कानूनी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे।
- इन सुझावों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करेंगी।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (2026):

- मूल्यांकन रिपोर्ट और नीतिगत सुझावों के आधार पर 2026 के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
- यह एक्शन प्लान सहकारी क्षेत्र में संरचनात्मक और नीतिगत बदलाव लाने में सहायक होगा।

संयुक्त राष्ट्र को समग्र प्रतिवेदन:

- IYC-2025 के दौरान की गई सभी कार्यवाहियों पर आधारित समग्र प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

यह कार्ययोजना सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और उसकी स्थायित्व व प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलें

'सहकार से समृद्धि'

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

भारत INDIA | अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2024 | 500 INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES 2025

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करे –

Website - https://www.cooperation.gov.in/

@minofcooperatn